● वर्ष : 17 ● अंक : 171 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शनिवार 11 अप्रैल 2026

बंगाल में सरकार बनती है तो प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा : अमित शाह

एजेंसी। कोलकाता

पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी का 'संकल्प पत्र' जारी किया। इस घोषणा पत्र में घुसपैठ पर सख्ती, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा गया है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठ के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 'पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो' (डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट) की नीति के तहत प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और मवेशी तस्करी पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई। राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी रिक्त सरकारी पदों को केवल योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। नकद के बदले नौकरी जैसी अनियमितताओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्थायी नौकरियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही। युवाओं के लिए घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट देने की भी घोषणा की गई है। आर्थिक विकास के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भूमि नीति में बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य में चार नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनके स्थान बाद में तय किए जाएंगे। पूर्व मेदिनीपुर जिले में हल्दिया बंदरगाह के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। साथ ही ताजपुर और कुलपी में गहरे समुद्री बंदरगाह विकसित करने की योजना है। चाय और जूट उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा पश्चिम बंगाल को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त परिवहन की सुविधा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेष समिति से कराने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।

बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र जारी

यूसीसी से लेकर महिलाओं को 3000 रुपये तक के बड़े वादे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना बहुप्रतीक्षित चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस घोषणापत्र को जारी किया, जिसे पार्टी ने 'भरोसा पत्र' नाम दिया है। इस संकल्प पत्र में महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों समेत विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए गए हैं। घोषणापत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह दस्तावेज़ बंगाल में "सोनार बांग्ला" के निर्माण का आधार बनेगा। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं, जिससे अब राज्य में बदलाव की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के घोषणापत्र में सबसे प्रमुख वादों में महिलाओं को हर महीने 3000रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल है, जो हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को भी 3000 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया गया है। पार्टी ने दावा किया है कि सत्ता में आने पर एक करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान : सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाएगा और सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में सभी केंद्रीय योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत, को पूरी तरह लागू करने की बात कही गई है। घोषणापत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

एनर्जी संकट से क्यों जूझ रहा है भारत?

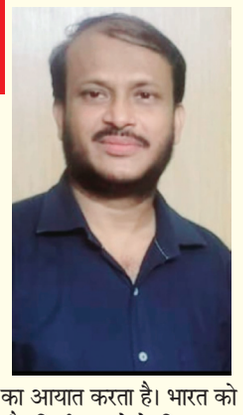

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद सारी दुनिया के देशों में जिस तरह से एनर्जी संकट देखने को मिल रहा है, वह अपने आप में भयाक्रांत करने वाली स्थिति है। भारत अपनी ऊर्जा की लगभग 85 फ़ीसदी ज़रूरतें आयात से पूरा करता है। भारत बड़ी मात्रा में खाद का आयात भी कर रहा है। चीन को भी भारी मात्रा में कच्चे तेल और गैस की जरूरत होती है। चीन पिछले कई वर्षों से कोयले के माध्यम से जिस तरह से अपनी ऊर्जा की जरूरत को लगातार बढाता जा रहा है। इस संकट में चीन ने अपने आप को किस तरह से बचाकर रखा है। भारत क्यों नहीं अपने आप को बचा पाया। इसका विश्लेषण करना जरूरी है। भारत चीन एवं अन्य देशों से खाद का आयात करता है। भारत को खाद संकट से जूझना पड़ रहा है। ऊर्जा संकट होने के बाद भी चीन अपनी जरूरत और निर्यात करने के लिए खाद का उत्पादन किस तरह से कर पा रहा है।

यह जानने की भारत सरकार को जरूरत है। चीन के पास गैस फील्ड ना के बराबर है। इसके बाद भी वह कोयला से गैस बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। पिछले वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में तकनीकी और पूंजी मे बड़ा निवेश किया है। चीन 80 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष एमएमटीपीए गैस का उत्पादन कर रहा है। भारत चीन के मुकाबले में मात्र 3.5 फ़ीसदी ही कोयले से गैस बना पा रहा है। कोयला चीन और भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत अपने कोयले से गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर कर सकता था। भारत ने इस पर ना तो ध्यान दिया, ना ही इस तरह की नीतियां बनाईं। देश पर हमारे पास जो संसाधन हैं उसका हम उपयोग कर सकें। ऊर्जा के लिए हम विदेशों के ऊपर आश्रित हैं। पिछले 20 वर्षों में हम आयात पर निर्भरता कम नही कर सके।

2007 में यूपीए सरकार ने कोयले से मीथेन गैस बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की थी। रानीगंज में एक छोटा पायलट संयंत्र शुरू किया गया था, उसके बाद भारत सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण भारत मीथेन गैस के उत्पादन में बुरी तरह से पिछड़ गया है। मोदी सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। 2020 में मोदी सरकार ने नेशनल कोल गैसीफिकेशन के काम की शुरुआत की। 2030 तक इसमें 100 एमएमटीपीए कोल के इस्तेमाल से गैस उत्पादन का लक्ष्य बनाया गया था। इसके लिए चार लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना था। इस योजना के लिए पिछले वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है, जिसे संतोषप्रद कहा जा सके। पिछले 6 वर्षों में इस योजना में कुल 5 एमएमटीपीए का ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। चीन की तुलना में भारत बुरी तरह से पिछड़ गया है। भारत सरकार और नीति आयोग की वेबसाइट हैं। उसके अनुसार कोयला से गैस उत्पादन की सात परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें 64000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह सारी योजनायें सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू की जानी थी।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

चुनाव से पहले हुमायूं को बड़ा झटका ओवैसी की पार्टी ने तोड़ा गठबंधन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम ने उनकी पार्टी 'आम जनता विकास पार्टी' के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब एआइएमआइएम राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि हुमायूं कबीर के हालिया बयान से मुस्लिम समाज की ईमानदारी और आत्मसम्मान पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में एआइएमआइएम किसी भी विवादित बयान से खुद को जोड़ना नहीं चाहती, इसलिए गठबंधन खत्म करने का फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को इस्लामपुर में हुमायूं कबीर और ओवैसी की संयुक्त रैली होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह गठबंधन टूट गया। इसके पीछे एक वायरल वीडियो को कारण बताया जा रहा है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर किसी व्यक्ति से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ विवादित बातें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चुनाव से ठीक पहले गठबंधन टूटना हुमायूं कबीर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि एआइएमआइएम ने साफ कर दिया है कि वह अब अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी।

उपराष्ट्रपति ने सिंधी भाषा में संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को सिंधी भाषा दिवस के अवसर पर सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। यह दो लिपियों- देवनागरी और फारसी में प्रकाशित किया गया है। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि विभाजन के बाद के कठिन समय में सिंधी भाषा ने दृढ़ता और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य किया। सिंधी में संविधान का प्रकाशन भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से लोग संविधान को अपनी मातृभाषा में समझ सकेंगे, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी और विश्वास मजबूत होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि यह पहल हमारी भाषाई विविधता, संवैधानिक जागरूकता और समावेशी भारत के संकल्प को और सशक्त बनाती है जो संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और लोकसभा सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे।

आसमान से गिरा क्रू मॉड्यूल और खिल उठे वैज्ञानिकों के चेहरे, इसरो ने गगनयान में रचा इतिहास

श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के अपने सपने गगनयान की ओर एक और विशाल कदम बढ़ा दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (आईएडीटी-02) को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह परीक्षण इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी सफलता ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा को पक्का कर दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस गौरवशाली उपलब्धि को देश के साथ साझा किया। इस परीक्षण की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक डमी क्रू मॉड्यूल को कई किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया गया। मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा तब होता है जब अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर ऊपर से वापस धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। उस वक्त मॉड्यूल की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसे सुरक्षित उतारने के लिए पैराशूट का सही क्रम में खुलना अनिवार्य

है। आईएडीटी -02 ने साबित कर दिया कि भारत का पैराशूट सिस्टम और रिकवरी तकनीक पूरी तरह सटीक है। गगनयान मिशन के तहत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित समुद्र में उतारना है। इसरो की इस सफलता ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि लैंडिंग के वक्त कोई अनहोनी नहीं होगी। यह मिशन अगले साल के लिए निर्धारित है और ऐसी हर कामयाबी भारत को उन गिने-चुने देशों की कतार में खड़ा कर रही है जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार, हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने संदेश में नीतीश कुमार और हरिवंश को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा।

सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताते हुए कहा कि कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। अंत में उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश के पत्रकारिता और

सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान के लिए कहा कि वे एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने गहन विचारों और अंतर्दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। उल्लेखनीय है कि, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के निवर्तमान उपसभापति हरिवंश ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में उनको शपथ दिलाई। 69 वर्षीय हरिवंश का पिछला कार्यकाल 09 अप्रैल को पूरा होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को उनको मनोनीत किया। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सीट रिक्त हुई थी। राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चुना जाता है।

लेबनान में इजराइली हमलों में लोगों की मौत पर भारत ने जताई चिंता

नई दिल्ली। भारत ने लेबनान में इजराइल के हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत पर शुक्रवार को गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत का हमेशा जोर रहा है कि आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम एशिया के हालात पर भारत की इस मुद्दे पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में इजराइल का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना और राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर हमले की खबर को परेशान करने वाला बताते हुए प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के ये सैनिक देश में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। लेबनान में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे स्थानीय मिशन लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ईरान-अमेरिका के बीच युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में इजराइल हमले कर रहा है। इससे युद्ध के दोबारा शुरू होने की आशंका बढ़ने लगी है।

असम में ऐतिहासिक सबसे ज्यादा 85.91 प्रतिशत मतदान तो पुडुचेरी में करीब 90 फीसद पड़े वोट

नई दिल्ली। देश के दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान देखने को मिला। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार को भारी मतदान दर्ज किया गया, जिसे लोकतंत्र के प्रति लोगों की मजबूत भागीदारी बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार असम में राज्य गठन (1950) के बाद पहली बार सबसे अधिक 85.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में 84.7 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि असम राज्य की 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। 35 में से 26 जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। साउथ सलमारा मनकचर जिले में सर्वाधिक 95.56

केरल में भी सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड

प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में सबसे कम 75.25 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई। वहीं केरल में 1987 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। राज्य में 78.27 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 140 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 2.6 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और 883 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

ज्ञान को धन में परिवर्तित करने को तकनीक के साथ कुशल कार्यबल, अनुसंधान भी जरूरी: गडकरी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि ज्ञान को धन में परिवर्तित के लिए नवाचार, विज्ञान तथा तकनीक के साथ-साथ कुशल कार्यबल और निरंतर अनुसंधान पर जोर देना आवश्यक है। गडकरी ने निर्माण उद्योग विकास परिषद की ओर से यहां आयोजित 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार और प्रदर्शनी 'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा ,"वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए निर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता से समझौता न करना और शॉर्टकट से बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए यह जरूरी है कि तत्काल निर्णय लिए जाएं, परियोजना योजना अच्छी हो और काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अगर हम नई तकनीक अपनाएं और काम करने के तरीके को सुधारें तो परियोजनाओं की लागत काफी कम हो सकती है। इसके लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और जरूरी मंजूरियों को पहले ही निपटाया जाए क्योंकि पहले की देरी और प्रशासनिक बाधाओं ने प्रोजेक्ट की समयसीमा और ठेकेदारों के बजट को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में केवल कम लागत ही नहीं बल्कि गुणवत्ता और प्रदर्शन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना चाहिए। इससे न केवल पेट्रोल-डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी बल्कि खर्च भी घटेगा। साथ ही सड़क बनाने में प्लास्टिक कचरे और पुराने टायरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय अवसंरचना कंपनियों ने दुबई, कतर और कई अफ्रीकी देशों में प्रमुख परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करके वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

सीनियर अफसरों को महीनों से वेतन नहीं, बेड़े में महज 13 अपने विमान बचे, मार्केट शेयर भी घटा

स्पाइसजेट में 20 फीसद स्टाफ की छंटनी, आर्थिक संकट गहराया

एजेंसी। नई दिल्ली

देश की निजी एयरलाइन स्पाइसजेट गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। परिचालन क्षमता में गिरावट के बीच कंपनी ने करीब 20 फीसद स्टाफ को कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत 500 से अधिक कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन स्पाइसजेट के पास वर्तमान में लगभग 6,800 कर्मचारी हैं, लेकिन इसके अपने विमान घटकर केवल 13 रह गए हैं, जिनमें 10 बोइंग और 3 क्यू400 शामिल हैं। इसके अलावा 14 विमान वेट-लीज पर संचालित किए जा रहे हैं। कंपनी के अंदर वित्तीय दबाव साफ नजर आ रहा है। सीनियर अधिकारियों को जनवरी से वेतन नहीं मिला है, जबकि अन्य कर्मचारियों की सैलरी भी 2-3 महीने की देरी से दी जा रही है। इसके साथ ही कंपनी पर जीएसटी, टीडीएस और पीएफ से जुड़े 100 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया हैं। घरेलू एविएशन बाजार में भी स्पाइसजेट की स्थिति कमजोर हुई है। कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है, जबकि नई एयरलाइन अकासा एयर 4.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ आगे निकल गई है।

कर्मचारियों में बढ़ा असंतोष व नाराजगी : कंपनी ने इस्तीफा दे चुके कई इंजीनियरों का नोटिस पीरियड भी समाप्त कर उन्हें तुरंत कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। वहीं, पुराने कर्मचारियों को फुल एंड फाइनल भुगतान न मिलने से नाराजगी बनी हुई है।

पायलटों के लिए नए नियम लागू : पायलटों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत उन्हें 21 दिन काम और 9 दिन छुट्टी दी जाएगी। इससे कैप्टन्स का मासिक वेतन 7.5 लाख रुपए से घटकर करीब 6 लाख रुपए रह जाएगा। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का घाटा 35 प्रतिशत बढ़कर 621 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 458 करोड़ रुपए था। वहीं, ऑपरेशनल रेवेन्यू भी घटकर 792 करोड़ रुपए रह गया। इस स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते घाटे, घटते बेड़े और कर्मचारियों की असंतुष्टि के चलते कंपनी के सामने आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा

नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज जस्टिस वर्मा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। जस्टिस वर्मा ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले में जजेज इन्क्वायरी एक्ट के तहत जांच कमेटी कमेटी गठित कर दिया है। लोकसभा स्पीकर की ओर से इन्क्वायरी के आदेश को जस्टिस वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 22 मार्च, 2025 को इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया था। जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली उच्च न्यायालय के जज थे तब उनके घर पर 14 मार्च, 2025 को आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग ने कैश बरामद किया था।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, अब्बास अंसारी बने रहेंगे विधायक

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) विधायक अब्बास अंसारी को उच्चतम न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सजा पर रोक के फैसले को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी। दरअसल, हेट स्पीच के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अब्बास अंसारा को सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी के विधायक पद पर खतरा मंडराने लगा था। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती देकर कहा था कि उच्च न्यायालय का फैसला गलत है और सजा पर लगी रोक हटाई जानी चाहिए।

मनी लांड्रिंग मामले में गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को मिली नियमित जमानत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को मनी लांड्रिंग के मामले में नियमित जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने नियमित जमानत देने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील को स्वीकार किया कि जमानत के आदेश में की गई टिप्पणी से केस के ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2025 को महेश लांगा को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की रोजाना सुनवाई करे। कोर्ट ने महेश लांगा से कहा था कि वो सुनवाई के दौरान कोई भी स्थगन की मांग नहीं करें। कोर्ट ने महेश लांगा को निर्देश दिया था कि वो अपने खिलाफ चल रहे इस मामले पर अखबार में कोई लेख न लिखें। इसके पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई, 2025 को महेश लांगा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जमानत मिलने से अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंच सकता है। लांगा को 2024 में जीएसटी के एक फर्जीवाड़ा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मनी लांड्रिंग का भी मामला दर्ज कर दिया गया।

जाति जनगणना रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, याचिकाकर्ता को फटकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2027 में होने वाली जाति जनगणना पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसकी याचिका की भाषा बदतमीजी से भरी हुई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये बदतमीजी की भाषा कहां से लेकर आते हैं आपलोग। कैसे लिखते हैं अपलोड पिटीशन। याचिका में जाति जनगणना 2027 पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया था कि आबादी के मुताबिक संसाधन का जिम्मेदारीपूर्वक बंटवारा हो। याचिका में कहा गया था कि एक बच्चे वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उच्चतम न्यायालय ने 2 फरवरी को भी जाति जनगणना के तरीके, उसके वर्गीकरण और सत्यापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। साल 2027 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। यह 1931 के बाद पहली बार है, जब व्यापक स्तर पर जाति आधारित गणना होगी।

प्रह्लाद जोशी ने आयातित इलेक्ट्रिक स्टोव की दिखाई एक झलक

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को एक ऐसी उन्नत तकनीक वाले आयातित इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में जानकारी दी जो बिजली का उपयोग करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की तरह आग की लपटें पैदा करता है। जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गुरुवार को एक भारतीय कंपनी ने एक आयातित स्टोव का प्रदर्शन किया, जो बिजली का उपयोग करके एलपीजी जैसी लौ उत्पन्न करता है। यह तकनीक वास्तव में बेहद प्रभावशाली और नवाचारी लगी। मैं चाहूंगा कि भारतीय निर्माता इस तकनीक को अपनाकर देश में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करें। जब इसे पीएम सूर्य घर जैसी योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जो सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती हैं, तो यह एलपीजी पर निर्भरता कम करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।

गाजियाबाद में नाबालिग से रेप-हत्या मामले में एसपी और जांच अधिकारी तलब

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गाजियाबाद में चार साल की लड़की के रेप और हत्या के मामले की लचर जांच पर पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी (आईओ) को तलब किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़िता के पिता के वकील एन हरिहरन की दलीलों पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने जांच में काफी लापरवाही बरती है। लड़की के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। दो निजी अस्पतालों ने भी लड़की का इलाज करने से इनकार कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने दोनों अस्पतालों को उनकी असंवेदनशीलता के लिए फटकार लगाई। दरअसल, 16 मार्च को पीड़िता को उसका पड़ोसी चॉकलेट खरीदने के बहाने बाहर ले गया। जब लड़की नहीं लौटी, तो उसके पिता ने काफी खोजबीन की। बाद में लड़की खून से सनी हुई बेहोशी की हालत में मिली। बाद में लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मधु विहार में बदमाशों ने बैग लूटकर की हवाई फायरिंग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। मधु विहार थाना क्षेत्र में गुरुवार रात जोशी कॉलोनी, आईपी एक्सटेंशन इलाके में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक कारोबारी परिवार को निशाना बनाते हुए करीब एक लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। वारदात के दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब 10:30 बजे की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह सेक्टर-62, नोएडा में थोक एफएमसीजी कारोबार चलाते हैं। वह परिवार और एक कर्मचारी के साथ घर लौटे थे। जैसे ही वे रॉयल बैंक्वेट हॉल के पास गाड़ी से उतरकर घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। आरोपितों में से एक ने पिस्टल निकालकर उन्हें धमकाया और उनके पास मौजूद बैग छीन लिया, जिसमें करीब एक लाख रुपये नकद थे। अचानक हुई इस वारदात से परिवार के लोग घबरा गए, लेकिन शोर सुनकर एक अन्य सदस्य ने हिम्मत दिखाते हुए कार से बदमाशों का पीछा किया।पीछा करने के दौरान परिवार के सदस्य ने बदमाशों की बाइक को टक्कर भी मारी, लेकिन इसके बावजूद आरोपित मौके से भागने में सफल रहे। भागते समय उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में आरोपित लूटा हुआ बैग और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी मौके पर फेंककर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मधु विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपितों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके।

डीयू में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के आर्ट्स फैकल्टी में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में आयोजित हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत की। इस मौके पर डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, डीयू दक्षिणी परिसर की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, एसओएल की निदेशक प्रो. पायल मागो और रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता सहित प्रिंसिपल, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रशासन और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना समय की आवश्यकता है। जब महिलाएं निर्णय लेने वाले पदों पर पहुंचेंगी, तभी वे समाज, परिवार और अपनी जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी बदलाव ला सकेंगी। दिल्ली में चलने वाली 'लखपति बिटिया' और 'अनमोल' जैसी योजनाएं इसी संवेदनशील दृष्टिकोण का परिणाम हैं, जो महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं। कार्यक्रम के दौरान 'अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है' और 'सशक्त नारी, समृद्ध राष्ट्र' जैसे संदेशों के माध्यम से महिला नेतृत्व और समान प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह 'बेटी बचाओ' से 'बेटी बढ़ाओ' तक की यात्रा को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग दशकों पुरानी है। 1931 से शुरू हुई यह पहल कई चरणों से गुजरी और वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का कानून बनना इस लंबे संघर्ष का परिणाम है और अब इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बनें और महिला सशक्तीकरण के इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दें। जब महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबरी से भाग लेंगी, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत बनेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया अध्याय लिखेगा और भारत को एक अधिक सशक्त, संतुलित और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा, शिक्षकों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस ऐतिहासिक पहल के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराया। यहां उपस्थित नागरिकों से अपील की गई कि वे इस पहल के समर्थन में आगे आएं और निर्धारित नंबर 9667173333 पर मिस्ड कॉल देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हस्ताक्षर अभियान के बाद मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित चाय स्टॉल पर छात्राओं और महिला शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी के साथ चाय पीते हुए उनकी राय, अनुभव और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस आत्मीय बातचीत के माध्यम से मुख्यमंत्री ने न केवल युवाओं और शिक्षकों से सीधा संवाद स्थापित किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच संवाद जितना सरल और सहज होगा, नीतियां उतनी ही प्रभावी और जनोन्मुखी बनेंगी।

इफको द्वारा देशव्यापी एकीकृत नैनो उर्वरक जागरूकता महा अभियान की शुरुआत की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : इफको (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड), भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था, ने आज औपचारिक रूप से इफको नैनो उर्वरक जागरूकता महा अभियान का शुभारंभ किया — यह एक व्यापक एकीकृत राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों के बीच नैनो उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। लॉन्च कार्यक्रम इफको सदन, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें इफको के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने उद्घाटन किया। इफको के प्रबंध निदेशक श्री के. जे. पटेल ने भी इस अवसर पर अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम को सुशोभित किया। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से आरंभ हुआ है और 'आत्मनिर्भर भारत' तथा 'सहकार से समृद्धि' के राष्ट्रीय मिशनों के अनुरूप है। इस पहल को माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जे. पी. नड्डा जी का भी विशिष्ट समर्थन प्राप्त है। भारत के राजपत्र के उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में नैनो एनपीके लिक्विड (8-8-10) और नैनो एनपीके ग्रेन्युलर (20-10-10) की ऐतिहासिक अधिसूचना को भारत की कृषि नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया। उन्होंने आगे कहा कि कोयंबटूर स्थित इफको-नैनोवेंशन्स में इफको का इनोवेशन हब और ब्राजील में आगामी नैनो उर्वरक विनिर्माण संयंत्र — जो जून 2026 तक चालू होने के लिए तैयार है — कृषि के लिए नैनोतकनीक में भारत की बढ़ती वैश्विक क्षमता का प्रमाण हैं। इस अवसर पर बोलते हुए इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने कहा कि भारत आज उस ऐतिहासिक संगम पर खड़ा है जहाँ परंपरा और तकनीक मिलती हैं, और यही संगम भारतीय कृषि को एक नई दिशा दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि गाँवों और किसानों से प्रवाहित होनी चाहिए, और 'आत्मनिर्भर भारत' तभी साकार हो सकता है जब किसान सशक्त और समृद्ध हो। उन्होंने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र — जिसके तहत सहकारी संस्थाएँ किसानों तक नई तकनीक और संसाधन पहुँचाने का माध्यम बन रही हैं — इस अभियान की भावना को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है और सही मायने में 'आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि' के सार को समाहित करता है।

- इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने 5 नैनो प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर ऐतिहासिक अभियान का शुभारंभ किया
- अभियान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 560 जिलों और 3,477 तहसीलों में व्यापक रूप से चलेगा
- नैनो एनपीके लिक्विड (8-8-10) और नैनो एनपीके ग्रेन्युलर (20-10-10) को भारत के उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया
- प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर और डिजिटल मीडिया पर आधारित बहु-माध्यम अभियान
- ब्राजील में इफको का नैनो उर्वरक विनिर्माण संयुक्त उद्यम जून 2026 तक चालू होने के लिए तैयार

फर्जी लोन ऐप गिरोह का भंडाफोड़, दो और आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने "ऑपरेशन साइहॉक 4.0" के तहत फर्जी लोन ऐप के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पहले गिरफ्तार चार आरोपितों के बाद अब दो और शातिर ठगों को दबोचा है। आरोपितों की पहचान कपासहेड़ा निवासी करण कुमार (24) और शमी अहमद (27) के रूप में हुई है। इनके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें आपत्तिजनक व्हाट्सऐप चैट मिली हैं। दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने शुक्रवार को बताया कि, यह गिरोह लोगों को बिना गारंटी लोन देने का झांसा देकर ठगी करता था। लोन लेने के बाद पीड़ितों के मोबाइल का एक्सेस हासिल कर उनकी निजी तस्वीरों को मॉर्फ कर ब्लैकमेल किया जाता था। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपित पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्चुअल नंबरों के जरिए अन्य सदस्यों के संपर्क में थे। मामले की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा के एक संदिग्ध खाते से हुई, जिसे म्यूल खाता के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि यह खाता कपासहेड़ा निवासी नेहल बाबू के नाम पर है और इसमें ठगी की रकम जमा की जा रही थी। इसी आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस उपायुक्त के अनुसार पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर पहले चार आरोपितों को पकड़ा था। उनकी निशानदेही पर आगे कार्रवाई करते हुए करण और शमी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में करण ने बताया कि उसने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता शमी को दिया था, जिसे आगे राहुल नामक व्यक्ति को सौंपा गया। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ठगी की रकम को म्यूल खातों में जमा कर निकालता था और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था, ताकि ट्रांजैक्शन का पता न चल सके। आरोपित यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए पैसे मंगवाते थे। दोनों आरोपित पेशे से रैपिडो चालक हैं और आसानी से पैसे कमाने के लालच में साइबर अपराध से जुड़ गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार विदेश में बैठे हैंडलर्स से जुड़े हैं या भारत में ही कोई गिरोह इसे संचालित कर रहा है।

"सितार से सितारों तकः पं. रवि शंकर जी की 106वीं जयंती पर सजे सुर और नृत्य के रंग, नृत्यांगना प्रतिभा सिंह सम्मानित"

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र Sri Ram Centre, मंडी हाउस में Kathak Dharohar द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य महोत्सव "सितार से सितारों तक" का भव्य समापन हुआ। यह आयोजन भारत रत्न Pt. Ravi Shankar जी की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में 6, 7 और 8 अप्रैल 2026 को किया गया। इस विशेष महोत्सव में देशभर से आए प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय संगीत, कथक और अन्य पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्कृष्ट प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही प्रख्यात नृत्यांगना Pratibha Singh, जिन्हें उनके अतुलनीय योगदान और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें विशेष पुरस्कार और सम्मान पत्र प्रदान किया गया, जिसे पाकर उन्होंने इसे अपने गुरुजनों और कला के प्रति समर्पण को समर्पित बताया। आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय कला के प्रति प्रेरित करना और महान संगीतकार पं. रवि शंकर जी की विरासत को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में कला प्रेमियों, विद्यार्थियों और गणमान्य अतिथियों की भारी उपस्थिति रही। यह आयोजन न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव रहा, बल्कि भारतीय संगीत और नृत्य की आत्मा को अनुभव करने का एक यादगार मंच भी साबित हुआ।

उप राष्ट्रपति श्री सी पी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा दिवस पर भारतीय संविधान के सिंधी भाषा देवनागरी और फारसी लिपि में प्रकाशित पुस्तकों का किया विमोचन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली । राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने विश्वास जताया है कि एक न एक दिन सिन्ध पाकिस्तान से अलग होकर भारत का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि सिन्धी समुदाय ने अपने आपको कभी शरणार्थी नहीं वरन् सदैव पुरुषार्थी माना है और भारत और सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को भी कभी नहीं छोड़ा है । विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी शुक्रवार को नई दिल्ली के वाईस प्रेसीडेण्ट एनक्लेव में उप राष्ट्रपति श्री सी.पी.राधाकृष्णन द्वारा भारत के संविधान का सिंधी देवनागरी भाषा और फारसी लिपियों में प्रकाशित पुस्तकों के विमोचन समारोह को विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। समारोह में केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री अर्जुनराम मेघवाल और इन्दौर से लोकसभा के सांसद शंकर लाल नंदवानी सहित बड़ी संख्या में देश भर से आए सिन्धी समाज के लोग उपस्थित थे। समारोह का आयोजन विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड, प्रादेशिक इकाई द्वारा किया गया। समारोह में विधानसभाध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि हालांकि सिन्ध वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन आजादी से पहले यह भारत का अभिन्न हिस्सा था और आजादी के बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजन का दंश झेलने के बाद भी सनातन धर्म के खातिर सिंधी समुदाय के लाखों लोग अपने घर बार और करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ पाकिस्तान से विस्थापित हुए थे लेकिन उन्होंने आजादी के 79 वर्षों के बाद भी अपने देश भारत के प्रति अपनी आस्था को नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से अलग होकर सिन्ध फिर से भारत का अभिन्न अंग बन सकता है ।

म्यांमार के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कीर्तिवर्धन ने लिया हिस्सा

लोकतंत्र की शान

नेपीडॉ। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने म्यांमार के नए राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वह म्यांमार सरकार के निमंत्रण पर 8-11 अप्रैल तक म्यांमार के दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने म्यांमार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और साथ ही भारत-म्यांमार सहयोग के तहत एक स्कूल निर्माण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और विकास परियोजनाओं को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने यांगून में प्रवासी भारतीय और 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने

म्यांमार के साथ सांस्कृतिक संबंधों और आईसीसीआर के कार्यों पर चर्चा की। कीर्तिवर्धन सिंह ने अपने इस दौरे से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री, यू मिन मिन के साथ शामिल होकर मुझे खुशी हुई, जहां हमने

उड़द और अरहर के व्यापार पर द्विपक्षीय एमओयू के विस्तार के लिए 'पत्रों का आदान-प्रदान' होते देखा। उन्होंने कृषि के साथ-साथ खाद्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया। विदेश राज्यमंत्री ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मैंने म्यांमार के रणनीतिक समुदाय के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, जिनमें 'म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज', 'सेंटर फॉर पीस एंड रिकंसिलिएशन', 'रखाइन लिटरेचर एंड कल्चरल एसोसिएशन' और 'म्यांमार-इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन' शामिल थे। इसके अलावा यांगून विश्वविद्यालय और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से भी संवाद हुआ। भारत-म्यांमार सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने के विभिन्न क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। राज्यमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत भारतीय नौसेना के एक सर्वेक्षण पोत (सर्वे शिप) पर आयोजित एक कार्यक्रम के साथ की थी। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री ने एक पोस्ट में कहा आज यांगून में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत 'आईएनएस संध्याक' पर आयोजित 'डेक रिसेप्शन' में शामिल होकर गर्व का अनुभव हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बातचीत ने भारत और म्यांमार के बीच गहरे और सुस्थापित जुड़ाव को दर्शाया। आईएनएस संध्याक की यह यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित 'महासागर' दृष्टिकोण के अनुरूप है। विदेश राज्यमंत्री की यह दौरा भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और म्यांमार के साथ मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। साथ ही उनकी यह चार दिवसीय उच्च-स्तरीय आधिकारिक यात्रा 2021 के तख्तापलट के बाद म्यांमार में सैन्य नेतृत्व को भारत की स्वीकृति के संकेत के रूप में भी देखी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

सिरसी के विकास के नायक बने चेयरमैन कौसर अब्बास, एमएलसी से मुलाकात में दिखाई प्रतिबद्धता

लोकतंत्र की शान , सम्भल। सिरसी नगर पंचायत के चेयरमैन कौसर अब्बास ने क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी एवं पूर्व सांसद सत्यपाल सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में खासतौर पर नगर पंचायत सिरसी के विकास कार्यों को गति देने, साफ-सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही जवाहर लाल मेमोरियल इंटर कॉलेज, सिरसी के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने और आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए भी योजनाएं बनाई गईं। इस मौके पर मनोज कुमार रस्तौगी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। चेयरमैन कौसर अब्बास की सक्रियता और दूरदर्शिता की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। उनके प्रयासों से सिरसी में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि "हमारा लक्ष्य है कि सिरसी को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जाए, जहां शिक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक तक बेहतर तरीके से पहुंच सकें।"

निष्कर्ष: सिरसी के विकास को लेकर चेयरमैन कौसर अब्बास की प्रतिबद्धता और जनहित में उनकी पहल निश्चित ही क्षेत्र को प्रगति की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी।

श्री बालाजी महाराज जन्मोत्सव पर रामपुर में निकलेगी ऐतिहासिक शोभा यात्रा

» 58वां वार्षिक उत्सव, 44वीं विशाल शोभा यात्रा शनिवार 11 अप्रैल को होगी आयोजित

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। श्री बालाजी महाराज के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर रामपुर में इस वर्ष 58वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर 44वीं विशाल शोभा यात्रा का भव्य आयोजन शनिवार 11 अप्रैल को हनमत जन्मोत्सव के उपलक्ष में इस शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर नगर में तैयारियां जोरों पर हैं। यह शोभा यात्रा संस्थापक बाबालीन सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र महंत अभिषेक मिश्रा एवं उपमहंत आयुष मिश्रा के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार, श्री बालाजी महाराज की यह भव्य शोभा यात्रा गांधी समाधि से प्रस्थान करेगी, जहां विधिवत पूजा-अर्चना के बाद यात्रा नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी। शोभा यात्रा के दौरान रामपुर नगर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो जाएगा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। जगह-जगह भक्तों द्वारा स्वागत द्वार बनाए जाएंगे और नगर में भजन-कीर्तन, जयकारों, झांकियों और ढोल-नगाड़ों के साथ धर्ममय वातावरण बनेगा। आयोजकों ने रामपुर की जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर शोभा यात्रा में भाग लें और श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आयोजन रामपुर में गत वर्षो की भांति आस्था, परंपरा और भक्ति का एक भव्य उदाहरण रहा है आगे भी रहेगा शोभा यात्रा के आयोजन सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी।

नव मनोनीत भाजपा जिला उपाध्यक्षों का पोरुष अग्रवाल के आवास पर हुआ जोरदार स्वागत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर: सेवा,समर्पण और संगठन शक्ति, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे 'ग्राम/बस्ती अभियान' के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन भाजपा हसनपुर मंडल उपाध्यक्ष पोरुष अग्रवाल के मोहल्ला कायस्थान बस्ती स्थित आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल एवं जिला उपाध्यक्ष हिमांशु त्यागी द्वारा भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों के सम्मुख पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को साझा किया।जिला कार्यकारिणी में पुनः दायित्व मिलने पर मयंक अग्रवाल एवं हिमांशु त्यागी का पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही वरिष्ठ नेता अतुल गर्ग (पूर्व नगर अध्यक्ष), वरिष्ठ व्यापारी एवं भाजपा नेता अंकुर अग्रवाल एवं संजय शर्मा (निवर्तमान मंडल अध्यक्ष) का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष ममता शर्मा, मंडल मंत्री प्रमोद , बूथ अध्यक्ष धर्मवीर सैनी, अनुराग शर्मा, मयंक अग्रवाल बिट्टू,अनुपम अग्रवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

योगी सरकार की अभ्युदय योजना का कमाल, आरओ/एआरओ परीक्षा में 10 होनहारों के सपने हुए पूरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर सफलता की नई कहानी लिखते हुए चर्चा में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित आरओ/एआरओ परीक्षा परिणाम में इस योजना से जुड़े 10 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर नाम रोशन किया है। इन सफल अभ्यर्थियों में 9 पुरुष और 1 महिला हैं। यह दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिलने पर प्रतिभा किसी भी बाधा को पार कर सकती है।

उच्च गुणवत्ता की निःशुल्क कोचिंग, शांत वातावरण के साथ बेहतर खानपान की सुविधा-चयनित अभ्यर्थियों में चित्रकूट के दिवाकर सिंह, महोबा के दीपेश कुमार खरे, सहारनपुर के विशेष प्रजापति और मोहित कनौजिया, महोबा के प्रदीप राजपूत, बाराबंकी के संजीत कुमार वर्मा, लखनऊ के मृत्युंजय सिंह, पीलीभीत के अविनाश कुमार, खुशबू पटेल और औरैया के धर्मेंद्र शामिल हैं। सहारनपुर निवासी विशेष प्रजापति की सफलता खास तौर पर प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 37वीं रैंक हासिल की। विशेष प्रजापति ने बताया कि उन्होंने करीब 25 महीनों तक अभ्युदय योजना के तहत तैयारी की, जहां उन्हें उच्च गुणवत्ता की निःशुल्क कोचिंग, अनुशासित और शांत वातावरण के साथ-साथ बेहतर खानपान की सुविधा भी मिली।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दूसरे चरण में बच्चों को किया गया जागरूक

लोक तंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी , संभल। जनपद में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के दूसरे चरण के अंतर्गत थाना नखासा क्षेत्र के मौहल्ला रुकंदी सराय स्थित प्राथमिक विद्यालय नखासा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को विभिन्न आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई तथा विशेष रूप से छोटी बच्चियों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस अवसर पर पुलिस टीम द्वारा बच्चों को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर उनका लाभ उठा सकें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1076, 112, 1090, 1930 तथा एमएसके (आंतरिक संपर्क) नंबर के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों का तुरंत उपयोग करें। कार्यक्रम में मिशन शक्ति प्रभारी राखी सिंह के नेतृत्व में महिला आरक्षी नीतू, प्रियंका एवं शैली थाना नखासा की टीम मौजूद रही। इस दौरान थाना नखासा प्रभारी संजिव बालियान के निर्देशन में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया, जिसमें पुलिस टीम ने बच्चों को जागरूक करते हुए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। स्थानीय लोगों एवं विद्यालय स्टाफ ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समाज में सुरक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश देते हैं।

मिशन शक्ति 5.0: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान

लोकतंत्र की शान , संवाददाता: सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/सिरसी थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी सुधीर पवार एवं मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक रश्मि मलिक द्वारा किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 क्या है? मिशन शक्ति 5.0 एक विशेष सरकारी अभियान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के दौरान उपनिरीक्षक रश्मि मलिक ने महिलाओं और बालिकाओं को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी दी तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

मिशन शक्ति 5.0 के प्रमुख 5 बिंदुओं पर दी गई जानकारी:

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना: उपनिरीक्षक रश्मि मलिक ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ाई गई है तथा एंटी-रोमियो टीम लगातार निगरानी रख रही है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

जागरूकता अभियान: चौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों एवं सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, ताकि वे जागरूक बन सकें।

हेल्पलाइन सुविधा: महिलाओं को 1090, 112 जैसी हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में बताया गया, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके।

सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने एवं आत्मरक्षा के गुर सीखने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें।

अपराधों पर सख्त कार्रवाई: महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर पुलिस द्वारा त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी सुधीर पवार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से उन्हें हर संभव सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाएगी। "महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस सदैव तत्पर है।"

रामपुर: कोतवाली पुलिस ने 4 नशा तस्करों को दबोचा, नए एसपी के चार्ज लेते ही तेज हुई कार्रवाई

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। रामपुर में नए पुलिस अधीक्षक के चार्ज संभालते ही जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने नशा बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से जिले में नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नए एसपी के निर्देश पर की गई, जिसके चलते पुलिस अब अपराध और नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही है। हालांकि, दूसरी ओर थाना गंज क्षेत्र को लेकर पुलिस की सक्रियता पर सवाल भी उठ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो थाना गंज क्षेत्र में नशे का कारोबार काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन वहां पुलिस की कार्रवाई अभी भी शांत नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार सड़ा खाड़वाड़ क्षेत्र में नशा तस्कर सबसे ज्यादा सक्रिय बताए जा रहे हैं, जहां खुलेआम नशे का कारोबार होने की चर्चाएं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि थाना गंज क्षेत्र में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाए तो नशा कारोबारियों पर पूरी तरह लगाम लग सकती है। फिलहाल कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता की चर्चा तेज हो गई है और लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरे जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान और तेज होगा।

एक रात, जब ईसीजी भी नसीब नहीं था:आज वही प्रदेश जीवन बचा रहा

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। सीएसआई के एनआईसी-2026 सम्मेलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के भीड़ भरे सभागार में जब डॉ. शरत चंद्रा ने बोलना शुरू किया, तो उनका स्वर सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, बल्कि एक बेटे का भी था जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की सीमाओं को बहुत करीब से महसूस किया था। उन्होंने वर्ष 2005 की एक घटना साझा की। उन्होंने बताया कि दिसंबर की एक रात करीब 10 बजे चंदौसी स्थित उनके घर से पिता का फोन आया कि बेटा सीने में दर्द हो रहा है, क्या करूं? एक डॉक्टर बेटे के रूप में उन्होंने सहज ही कहा- पापा, कहीं पास में जाकर ईसीजी करा लीजिए। पिता ने कहा कि इस समय रात में ईसीजी कहां हो पाएगा, सुबह ही कराएंगे। डॉ. चंद्रा ने कहा कि उस रात सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मैं भी जागता रहा। अगले दिन ईसीजी सामान्य आया, लेकिन वह रात उनके मन में एक सवाल छोड़ गई कि क्या हमारे पास समय पर इलाज की व्यवस्था है? उन्होंने कहा कि आज, दो दशक बाद, उसी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल चुकी है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब दिल का दौरा पड़ने पर मरीज को सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ता। 'हृदय सेतु' जैसे प्रयासों ने बड़े संस्थानों जैसे एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को जिला अस्पतालों से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जहां एंजियोप्लास्टी जैसे उपचार केवल बड़े शहरों तक सीमित थे, वहीं अब सुल्तानपुर, जौनपुर, बहराइच, गोंडा और बस्ती जैसे जिलों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। अब मरीज को केवल दूरी नहीं, बल्कि समय से भी लड़ना नहीं पड़ता।

बिलासपुर: धर्मस्थल के निकट शराब की दुकान खोलने के विरोध में सांसद मोहिबुल्ला नदवी का कड़ा रुख

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर । जिलाधिकारी ने तत्काल समस्या के समाधान के निर्देश बिलासपुर रामपुर बिलासपुर मे रामपुर रोड पर एक धर्मस्थल के अत्यंत निकट खोली जा रही देशी मदिरा की दुकान को लेकर स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। नियमों को ताक पर रखकर शराब सिंडिकेट के प्रभाव में खोली जा रही इस दुकान से धार्मिक भावनाएं आहत होने और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को देखते हुए माननीय सांसद श्री मोहिबुल्ला नदवी जी ने इस गंभीर प्रकरण का त्वरित संज्ञान लिया है। सांसद प्रतिनिधि अथर अली खां ने इस पूरे मामले से सांसद महोदय को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर पवित्र स्थल के पास शराब की दुकान का संचालन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी है। प्रशासनिक कार्यवाही और निर्देश: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय सांसद मोहिबुल्ला नदवी जी ने तत्काल जिलाधिकारी महोदय और जिला आबकारी अधिकारी से फोन पर वार्ता की। सांसद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनभावनाओं और धार्मिक मर्यादाओं के विरुद्ध किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दुकान के संचालन पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसे किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। अधिकारियों का आश्वासन :सांसद जी के कड़े रुख के बाद जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी ने प्रकरण की जांच कर शीघ्र ही दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने का ठोस आश्वासन दिया है। सांसद जी के दिशा-निर्देशन में एक औपचारिक प्रार्थना पत्र भी जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है, ताकि वस्तुस्थिति के अनुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।: माननीय सांसद मोहिबुल्ला नदवी जी ने कहा कि प्रशासन का कर्तव्य जनता की भावनाओं और नियमों का सम्मान करना है। शराब सिंडिकेट के किसी भी दबाव को हावी नहीं होने दिया जाएगा और क्षेत्र की शांति व धार्मिक शुचिता को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

बिजनौर के नांगल मे इंस्टाग्राम पर हथियारों का प्रदर्शन और भड़काऊ वीडियो मामले में बड़ा खुलासा, दो गिरफ्तार, तीन विदेश में फरार

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर भड़काऊ विचार फैलाने के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। थाना नांगल में दर्ज मुकदमा संख्या 156/25 में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन मुख्य आरोपी विदेश में होने के चलते उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार, दिनांक 23 नवंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें आकिब नामक युवक अपने साथियों के साथ लाइव आकर शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहा था। यह वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट किया गया था। मामले में पुलिस ने धारा 7/25(1)(ए) आर्म्स एक्ट और धारा 69(ए) आईटी एक्ट के तहत आकिब, मैजुल व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रारंभिक विवेचना में लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येन्द्र मलिक को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच थाना प्रभारी नजीबाबाद को सौंप दी गई। अग्रिम जांच में चार आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें मैजुल (निवासी सौफतपुर), आकिब (निवासी सठला, मेरठ), आजाद (निवासी मंडावर क्षेत्र) और उवैद मलिक शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि मैजुल वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका, जबकि आकिब और आजाद सऊदी अरब में रह रहे हैं। इन तीनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने उवैद मलिक को गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ में जलाल हैदर उर्फ समीर जाफरी का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने समीर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उवैद ने बताया कि वह गुजरात के सूरत में काम के दौरान समीर के संपर्क में आया था, जहां से उसकी पहचान आकिब और मैजुल से कराई गई। आरोप है कि आकिब इंस्टाग्राम लाइव के जरिए कट्टरपंथी और भड़काऊ विचार फैलाता था तथा हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता था। वह अपने फॉलोअर्स को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, गाड़ियां जलाने और विरोध करने वालों को धमकाने के लिए प्रेरित करता था। उवैद ने यह भी खुलासा किया कि लाइव के दौरान आकिब द्वारा ए.के.-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार दिखाए जाते थे और भारत में नेटवर्क तैयार कर युवाओं की भर्ती करने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों द्वारा भविष्य में बड़े आपराधिक और देशविरोधी कृत्यों की साजिश रची जा रही थी। वहीं, समीर जाफरी ने पूछताछ में बताया कि उसने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को आकिब और मैजुल से जोड़ने और उनके विचारों का प्रचार-प्रसार करने में भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दुकान से कब्जा हटवाया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में किरायेदार से दुकान को खाली करा दिया गया। कार्रवाई को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। शुक्रवार को संभल रोड स्थित एक मेट व पर्दे की दुकान पर पुलिस बल कोर्ट के आदेश के साथ पहुंच गया। बताया जाता है कि स्व0 शाहिद खान पुत्र मकसूद खान ने सालों पहले तनसीर खान को दुकान किराये पर दी थी। दुकान स्वामी के पुत्र का आरोप था कि किरायेदार न तो उन्हें किराया दे रहा था और न ही दुकान को खाली कर रहा था। उसने उनकी दुकान पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर मामला कोर्ट में चला गया था। शुक्रवार को कोर्ट अमीन कोतवाल राजेश कुमार तिवारी व भारी पुलिस बल के साथ दुकान पर पहुंच गये। पुलिस ने दुकान को खाली करवाने के बाद दुकान स्वामी के हवाले कर दिया। दुकान स्वामी ने बताया कोर्ट के आदेश से दुकान पुलिस की मौजूदगी में खाली हो गई है। वह कोर्ट के आदेश से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि यह न्याय की जीत हुई है। करवाई देखने के लिए दुकान के आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी।

भारतीय किसान संघ ने ग्रामीणों की समस्याओ को लेकर D M से किया पत्राचार

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा /गंगेश्वरी: भारतीय किसान संघ खण्ड गंगेश्वरी के अध्यक्ष दिव्यांशु यादव व भारतीय किसान संघ के अमरोहा जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शर्मा ने गंगेश्वरी क्षेत्र के ग्राम पौरारा में मुख्य मार्ग पर बाबा हरिशंकर आश्रम के सामने व प्राचीन देवी मंदिर के सामने जल भराव की समस्या व ग्राम रहरई मे खेल मैदान की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराकर खाली कराने जैसी जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय अमरोहा को अवगत कराकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा की है, गंगेश्वरी खण्ड की मासिक बैठक के दौरान पौरारा में जल भराव की समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन दिया था लेकिन कोई समाधान नही हुआ, गंगेश्वरी खण्ड अध्यक्ष दिव्यांशु यादव व जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने पत्राचार के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराकर समाधान कराने की पहल की है।

रामपुर में फर्जी क्राइम ब्रांच का सिपाही गिरफ्तार पत्नी के जरिए भी करता था अवैध वसूली

» पुलिस कार्यालय में पत्रकारों के लिए रही कुर्सियां नदारत कुर्सी रहीम कम

» नए कप्तान अपने पुलिस स्टाफ की छवि जानने में जुटे पत्रकारों से वार्ता तेजी लाने के लिए बाजार भाव का जरिया ढूंढा पत्रकारों

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। जनपद रामपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लोगों को धमकाने और अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से जिले में क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बनकर लोगों को डराता था और उनसे पैसे ऐंठता था। सूत्रों के अनुसार आरोपी न सिर्फ खुद अवैध वसूली करता था, बल्कि अपनी पत्नी के माध्यम से भी लोगों से पैसे मंगवाता था। आरोपी लोगों को क्राइम ब्रांच की कार्रवाई का डर दिखाकर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देता और फिर समझौते के नाम पर रकम वसूल करता था। पुलिस को जब इस फर्जी सिपाही की गतिविधियों की जानकारी मिली तो मामले की जांच कराई गई। जांच में आरोपी की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से पुलिस से संबंधित कुछ सामान और दस्तावेज भी बरामद होने की बात कही जा रही है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, अवैध वसूली और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अब तक कितने लोगों से वसूली की और इस पूरे गिरोह में और कौन-कौन शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनता को ऐसे फर्जी लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस या क्राइम ब्रांच का नाम लेकर डराने-धमकाने का प्रयास करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। फर्जी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में नवविवाहिता की हत्या, पोखर में जलाकर फेका

हाजीपुर। वैशाली में जंदाहा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या के बाद शव को घर से करीब 500 मीटर दूर चंवर के एक पोखर में जला दिया और अवशेषों को पोखर में फेंक दिया। यह घटना लक्ष्मीपुर बरबट्टा पंचायत के वार्ड संख्या 05 में हुई। बताया जा रहा है कि विवाहिता की हत्या रात के अंधेरे में की गई। इसके बाद ससुराल वालों ने देर रात को ही शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। शव पूरी तरह जल जाने के बाद, आरोपियों ने शव और लकड़ियों के अवशेषों को पोखर में फेंक दिया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय नीलम कुमारी के रूप में हुई है, जो रोहित कुमार की पत्नी थी। उनकी शादी लगभग 11 महीने पहले हुई थी। नीलम कुमारी जंदाहा थाना क्षेत्र के हुदहुदपुर गांव निवासी बिसुनधारी सिंह की पुत्री थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने घटनास्थल से लेकर विवाहिता के ससुराल तक की गहन जांच की है। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। इस संबंध में जंदाहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष की ओर से अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हाजीपुर में रोड एक्सीडेंट में महिला की मौत, रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर

हाजीपुर। वैशाली के हाजीपुर में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में 28 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के सुभाई चौक स्थित केनरा बैंक के सामने हुई। मौत के बाद गुस्सा लोगों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया। जिससे आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। मृतका की पहचान जंदाहा थाना क्षेत्र के दशप्रहा गांव निवासी सावित्री देवी के रूप में हुई है। उनके पति का नाम किशन राम है। पुलिस के अनुसार, सावित्री देवी सड़क पार कर रही थीं,

तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सावित्री देवी पिछले एक महीने से अपने मायके दौलतपुर आई हुई थीं। उनके पिता का नाम सुरेन्द्र दास है। बताया जा रहा है कि वह हाजीपुर से अपनी बहन को ट्रेन पकड़वाकर मायके लौट रही थीं। वह अपने सात भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके दो बेटे हैं। सावित्री देवी कोलकाता में रहती थीं और एक महीने पहले ही मायके आई थीं।

बहलोलपुर दियारा में भैंस चराने पर फायरिंग, वैशाली में 2 पक्षों के बीच विवाद, 3 जिलों की पुलिस पहुंची

हाजीपुर। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र अंतर्गत बहलोलपुर दियारा में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय थाना और डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही वैशाली, समस्तीपुर और पटना जिलों की पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, बहलोलपुर दियारा में भैंस चराने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई। यह विवाद धीरे-धीरे बढ़ा और दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई।

क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। बहलोलपुर दियारा क्षेत्र तीन जिलों और चार थाना क्षेत्रों में फैला हुआ है। मौके पर महनार, जुड़ावनपुर, पटोरी थाना और पटना की पुलिस टीम मौजूद है। महनार थाना अध्यक्ष के अनुसार, घटना स्थल जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो महनार थाना स्थल से लगभग तीन सौ मीटर दूर है। जिस किसान की जमीन को लेकर विवाद है, वह महनार थाना क्षेत्र का निवासी है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और सीमा निर्धारित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लकड़ी मिल में लगी आग:लाखों की लकड़ी और मशीनें जलकर राख, मालिक ने शॉर्ट सर्किट से किया इनकार

हाजीपुर। वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार स्थित एक लकड़ी मिल में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की कीमती लकड़ी, मशीनें और तैयार सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण को लेकर मिल मालिक और अग्निशमन विभाग के बयानों में विरोधाभास है। यह घटना बिदुपुर बाजार में भारत पेट्रोल पंप के उत्तर में स्थित अमरनाथ शर्मा मिल में बीती रात हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि मिल में रखा लाखों का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, मिल मालिक रात में मिल बंद कर घर चले गए थे। आग फैलने के बाद इसकी सूचना मिल मालिक और अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग की दमकल गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक मिल का अधिकांश सामान जल चुका था। मिल मालिक अमरनाथ शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि मिल बंद करते समय वे मुख्य बिजली आपूर्ति का स्विच पूरी तरह बंद कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल के बाहर रखी चौकी पर कुछ स्थानीय नशेड़ी गांजा और स्मैक का सेवन करते हैं, और उनकी जली हुई चिंगारी से आग लगी हो सकती है। मिल मालिक ने बताया कि लाखों के नुकसान के बावजूद वे इस घटना की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। उनका तर्क है कि मिल का बीमा नहीं है और न ही स्टॉक व मशीनों के मूल्य के कोई कागजात हैं, जिससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, अग्निशमन विभाग के दमकल चालक दीपक सिंह ने आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट ही बताया है। उन्होंने पुष्टि की कि मिल में रखी सभी कीमती लकड़ियां आग में पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

वैशाली में बाइक चोरी सीसीटीवी में कैद, चोर का चेहरा दिखा, मास्टर चाबी से खोला लॉक; फरार

हाजीपुर। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकोसन बाजार स्थित विनोद वस्त्रालय के सामने से एक स्प्लेंडर बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे चोरी की पूरी घटना स्पष्ट होती है। बाइक मालिक कुंदन यादव (पिता अनिल राय, ग्राम जहांगीरपुर श्याम, थाना चांदपुरा ओपी) ने बिदुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह घर से बाजार मार्केटिंग करने निकले थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी स्प्लेंडर बाइक (रजिस्ट्रेशन नंबरः BR31AE6704) को विनोद वस्त्रालय के सामने खड़ा किया और मार्केटिंग के सिलसिले में चले गए। जब वह वापस लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पता चला कि एक युवक आराम से बाइक के नजदीक पहुंचता है और मास्टर चाबी की मदद से लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। पूरी वारदात को अंजाम देने में चोर को महज कुछ सेकंड लगे। हालांकि, कैमरे के एंगल और रोशनी मे चोर का चेहरा साफ दिख रहा है। बाइक मालिक कुंदन यादव ने बताया कि वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ने के लिए खुद भी जुटा हुआ है। ओर प्रशासन को भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इधर, घटना को गंभीरता से लेते हुए बिदुपुर थाने की पुलिस सक्रिय हो गई है। सीसीटीवी फुटेज और चोर का फोटो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, ताकि लोगों की मदद से आरोपी की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल, पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर जांच कर रही है।

नीट छात्रा रेप-मौतः प्रदर्शन पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी

एजेंसी, पटना

पटना में NEET छात्रा रेप मौत मामले को लेकर शुक्रवार को सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। इनकम टैक्स चौराहे से भारी संख्या में प्रदर्शनकारी CBI ऑफिस का घेराव करने निकले। पुलिस ने सभी को इनकम टैक्स चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोका था। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और आगे निकलने की कोशिश करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, जहानाबाद से बसों के जरिए सैकड़ों लोग पटना पहुंचे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं।

लोग मामले में CBI जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन में शामिल मृतका की मां ने कहा, 'CBI जांच पर भरोसा नहीं है। मैं दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करती हूं। जल्द से जल्द CBI कार्रवाई करे।' मजिस्ट्रेट प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय टीम को सीबीआई दफ्तर लेकर गए हैं। सीबीआई अधिकारी से उनकी मुलाकात होगी।

पप्पू यादव बोले- जहाबाद की बेटी पर नेता क्यों चुप हैंः NEET छात्रा मामले को लेकर इस प्रदर्शन में सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि, 'इस देश का समाज दोषी है। हम लोग कायर सोसाइटी में हैं। आप फारबिसगंज की घटना नहीं देख रहे हो। CBI तो यह कह रही है कि पप्पू यादव ने प्रदर्शन करने के लिए कितने रुपए दिए।

कल एक जहानाबाद के मित्र से पूछ रहा था कि आप डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो, वॉर्डन की गिरफ्तारी क्यों

नहीं कर रहे हो, चार्ज शीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो, कोई बेटी सुरक्षित है क्या इन नेताओं से? चार बार लोकसभा में मामला उठा चुका हूं, क्यों कोई नेता बेटी के बारे में नहीं बोलता है। नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि, 'मुझे काहे का नोटिस मिलेगा। मैं 3 में ना 13 में हूं। मैं बेटी के लिए लड़ता रहा हूं

> ♦ मां बोली- सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं, बेटी का हत्यारा कौन, पप्पू यादव भी शामिल हुए

और जब तक जिंदा रहूंगा लड़ते रहूंगा।'

4 महीने हो गए, CBI किसी नतीजे तक नहीं पहुंचीः प्रदर्शन में शामिल पुष्कर आनंद ने कहा कि, '4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक CBI किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। यहां तक की चार्जशीट तक भी दाखिल नहीं हो पाई है। आखिर किसके दबाव में लीपापोती हो रही है। क्यों नहीं सीबीआई किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रही है। हम लोग चार्ज शीट दाखिल करने और मृतका को न्याय दिलाने के लिए इनकम टैक्स चौराहा से सीबीआई दफ्तर तक प्रदर्शन कर रहे हैं।'

महिला आयोग अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को करेगी जागरूक

एजेंसी, पटना

बिहार राज्य महिला आयोग अब गांव में जाकर महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करेगी। इसे लेकर अब गांव में कैंप लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम 'महिला आयोग आपके द्वार, जानिए अपने हक और अधिकार' रखा गया है। 11 अप्रैल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जो समस्तीपुर से शुरू होकर बिहार के विभिन्न जिलों में जाएगी। इस कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति हो रहे हैं अत्याचार और अन्याय के खिलाफ महिला आयोग वंचित महिलाओं से बातचीत करेगी और उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए सजग करेगी।

महिला आयोग गांव-गांव जाकर महिलाओं को सजग करेगीः बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो अप्सरा ने कहा कि गांव और प्रखंड की महिलाएं जो महिला आयोग को नहीं जानती हैं, तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें जागरूक किया जाए। इसलिए महिला आयोग अब गांव-गांव जाकर ऐसी महिलाओं को सजग करेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 अप्रैल से हो रही है और सबसे पहले हमने समस्तीपुर के एक गांव को चुना है। उजियारपुर और सरायरंजन के बॉर्डर पर स्थित एक गांव में हम लोग शुक्रवार को कैंप लगाने जा रहे हैं। दो प्रखंडों की वंचित महिलाओं का हमारे इस कैंप में स्वागत रहेगा।

1000 महिलाओं के आने की उम्मीदः अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को आमंत्रित किया गया है, ताकि वह आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 महिलाओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए जिले के डीएम को सूचित कर दिया गया है। महिला आयोग पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम करने जा रही है इससे पहले जिला मुख्यालय में कोई भी कैंप लगाया जाता था, जिसमें प्रताड़ित महिलाएं जाकर आवेदन देती थी। इस कैंप का लाभ शहरी महिलाएं ज्यादा उठा पाती थी क्योंकि वह पढ़ी-लिखी होती थी मगर गांव में रहने वाली वंचित महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है जिन्हें जागरूक करना जरूरी है।

किशनगंज के तत्कालीन एसडीपीओ गौतम कुमार पहुंचे पटना ईओयू दफ्तर

एजेंसी, पटना

किशनगंज के तत्कालीन एसडीपीओ गौतम कुमार की भ्रष्टाचार मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक नई संपत्ति का खुलासा होने के बाद शुक्रवार को पूछताछ के लिए फिर तलब किया है।

सिलीगुड़ी में दो मंजिला मकान का खुलासाः EOU की जांच के दौरान एक बेहद ही चौंकने वाला खुलासा हुआ था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गौतम कुमार के एक दो मंजिला मकान है। यह मकान उनकी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के नाम पर बागडोगरा निबंधन कार्यालय से जुलाई 2025 में पंजीकृत कराया गया था। इस नई संपत्ति के खुलासे के बाद EOU ने उन्हें दोबारा बुलाया है। हालांकि, EOU की टीम ने इसकी पुष्टि की थी की मकान का असली मालिक

गौतम कुमार ही है।

पहले भी हो चुकी है लंबी पूछताछः इससे पहले सोमवार को गौतम कुमार EOU दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ के बाद बिहार सरकार ने कार्रवाई करते हुए गौतम कुमार को निलंबित कर दिया था।

दस्तावेजों के साथ पेश होने का निर्देशः शुक्रवार को गौतम कुमार को दस्तावेजों के साथ EOU के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि इस पूछताछ के बाद भ्रष्टाचार मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं।

14.900 किलो गोल्ड लूट का खुलासा, 3 गिरफ्तार

एजेंसी, पटना

पटना में कस्टम अधिकारी बनकर स्वर्ण कारोबारी से करोड़ों का 14.900 kg गोल्ड लूटा गया था। इस मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया है। तीन आरोपियों को मेहंदी गंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पीसी कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया आरोपियों के पास से 5.400 ग्राम सोना, 9 राउंड गोली, 1.97 लाख रुपये कैश बरामद किये गए हैं। कारोबारी की पिछले डेढ़ साल से अपराधी रेकी कर रहे थे। कई बार चाय पीने के दौरान भी रेकी की गई। इस घटना में 8 से 9 अपराधी शामिल थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों में भी छापेमारी चल रही है।

घटना के बाद नौबतपुर भागे, ट्रेन से हुए फराराः इस कांड का मुख्य सरगना अमरनाथ उर्फ गोपी है, इसी ने पूरी लूट की प्लानिंग बनाई गई थी। गुड्डू ने गाड़ी उपलब्ध कराई थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश नौबतपुर गए थे। वहां से फिर ट्रेन के जरिए फरार हो गए थे। अपराधियों की गिरफ्तारी मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से हुई है। पकड़े गए अपराधियों का नाम अमरनाथ उर्फ गोपी, आदित्य गिरी उर्फ सोनी और संजय कुमार है। पूछताछ में पता चला है कि यूट्यूब देखकर कस्टम अधिकारी

बनने की प्लानिंग की थी। ताकि किसी को शक वगैरह नहीं हो।

डेढ़ साल से कर रहे थे कारोबारी की रैकीः पिछले डेढ़ साल से बदमाशों को कारोबारी के आने की सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आने से जाने तक एक डायरी में सब कुछ बदमाशों ने अपडेट किया था। घटना को अंजाम देने के बाद उसे जला दिया। मास्टरमाइंड अमरनाथ उर्फ गोपी शातिर बदमाश रहा है। इसके अपराधी के इतिहास में मिले हैं। डकैती के मामले में जेल भी जा चुका है। दरअसल, पटना में गुजरात के कारोबारी के स्टाफ से बीते शनिवार को 14.900 kg किलो सोने की लूट हुई थी। कस्टम अधिकारी बनकर अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया थी। ये वारदात दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में हुई थी। गुजरात के कारोबारी के स्टाफ और राजकोट

> ❑ डेढ़ साल से कारोबारी की कर रहे थे रैकी, यू-ट्यूब देख नकली कस्टम अधिकारी बने, फिर की लूटपाट

के रहने वाले महेश को पटना में बंधक बना लिया गया। उससे सोने से भरा बैग बदमाशों ने लूट लिया और इसके बाद महेश को छोड़कर फरार हो गए। लूटे गए 14.900 kg किलोग्राम सोने की कीमत आज के हिसाब से करीब 20 करोड़ से ज्यादा की होगी।

गुजरात के राजकोट निवासी महेश मामतोरा और प्रिंस रामपरिया नामक दो व्यापारी अहमदाबाद से सहरसा एक्सप्रेस के जरिए दानापुर पहुंचे थे। वे केबीएस एंड संस के मालिक सुनील भाई का सोने का जेवर लेकर पटना के बाकरगंज जा रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन से बाकरगंज जाने के लिए दोनों ने एक ऑटो बुक की। जैसे ही उनका ऑटो खगौल ओवरब्रिज के बीच पहुंचा, पुलिस का स्टीकर लगी एक कार और दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 से 7 बदमाशों ने दोनों को घेर लिया। सभी बदमाश सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए थे। उन्होंने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर जांच के नाम पर व्यापारियों के तीनों बैग जब्त कर लिए थे।

'बीजेपी के दबाव में राज्यसभा गए नीतीश कुमार'

> ♦ तेजस्वी ने कहा- विधानसभा में वो बोलते तो सदन स्थगित कर देते थे, नेता प्रतिपक्ष को मिली सैलरी

एजेंसी, पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। जल्द ही वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान ही महागठबंधन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह की राजनीतिक स्थिति नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन एनडीए के नेताओं ने जनता को गुमराह किया।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय एनडीए के नेता 25 से 30 साल तक नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कर रहे थे, लेकिन अब अचानक सरकार में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यही निर्णय लेना

था, तो चुनाव से पहले क्यों नहीं बताया गया। तेजस्वी ने कहा, यह फैसला नीतीश कुमार की इच्छा से नहीं बल्कि बीजेपी के दबाव में लिया गया है। उन्होंने बिहार की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने पूछा कि आम लोगों के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

TRE-4 के मुद्दे पर बोला हमलाः TRE-4 के मुद्दे को लेकर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी सुझाव दिए गए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि सरकार में बैठे लोग काम करने के बजाय केवल सत्ता बचाने में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्हें बिहार से ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है।

कहा- जनादेश कुछ और है, मुख्यमंत्री कोई और बन रहाः मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश कुछ और है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर दबाव होने का आरोप लगाते हुए कहा, कई मौकों पर उन्हें सार्वजनिक रूप से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा में जब नीतीश कुमार बोलते हैं, तो उनकी बात बीच में रोकी जाती है या सदन को स्थगित कर दिया जाता है, जो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार को दर्शाता है।

तेजस्वी को मिली सैलरीः तेजस्वी यादव ने कहा था सैलरी नहीं मिली है, अब उसपर सरकार का जवाब आया है। सरकार के मुताबिक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। 15 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक का बकाया वेतन 18 मार्च 2026 को कोषागार में भेजा गया था और उसी दिन पास भी हो गया। इसके बाद दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक का वेतन 10 अप्रैल 2026 को कोषागार में जमा किया गया, जिसे आज ही सुबह 11:28 बजे मंजूरी मिल गई। तेजस्वी यादव का पुराना और हाल का वेतन अब पास हो चुका है।

पटना यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन

एजेंसी, पटना

पटना यूनिवर्सिटी के छात्र शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे। छात्र यूनिवर्सिटी के दरभंगा हाउस में जुटे हैं। कॉलेज के छात्र अनुराग कुमार और वर्तमान काउंसलर मोहम्मद एहसानुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ छात्र जमकर हंगामा कर रहे। दरअसल, 30 मार्च को सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी कैंपस में बवाल हुआ था। उस दौरान दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी मौजूद थे।

छात्रों ने सम्राट चौधरी गो बैक, डीएम चोर है जैसे नारे लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर समेत 6 छात्रों को नामजद आरोपी बनाया था। इनके अलावा 30 अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। वहीं, दो लोगों को अरेस्ट किया गया था। छात्रों में भारी आक्रोश है। वो

> ❑ गृह मंत्री शर्म करो समेत कई नारे लगे, सीएम के सामने कैंपस में हुआ था हंगामा

लगातार कह रहे, निर्दोष छात्रों को रिहा करो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अबकी बार, बिहार सरकार होश में आओ, लोकतांत्रिक आवाजों को दबाना बंद करो, छात्रों पर मुकदमा वापस लो, गृह मंत्री शर्म करो जैसे नारे लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों पर पुलिसिया दमन नहीं सहेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा, पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी

एजेंसी, पटना

पटना सिविल कोर्ट के साथ बिहार विधानसभा को भी एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड की टीम ने विधानसभा और कोर्ट परिसर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। पीरबहोर थानेदार सज्जाद गद्दी ने बताया कि, 'मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी मिली है। फिलहाल, परिसर में तलाश जारी है।' हालांकि, कोर्ट को बंद नहीं कराया गया है। अदालती कामकाज जारी है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी कैंपस में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।' मेल में लिखा है- 'विधानसभा में 13RDX लगाए हैं। 2.15 बजे धमाकों के लिए तैयार रहो। विधायक और आम जनता को बाहर निकाल लो।' पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी

मिलने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया था। इसके बाद दावा किया जा रहा था कि अब इस तरीके की धमकी नहीं आएगी। बावजूद इसके पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ने की धमकी मिली है। इस बार धमकी मिलने पर वकीलों ने नाराजगी जाहिर की है। पटना सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिंह ने कहा कि, 'यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। बार-बार धमकी आ रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

बुडको ने 3 पक्के घाट किए तैयार, छठ में श्रद्धालुओं को मिलेगी कई सुविधाएं

एजेंसी, पटना

पटना में घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में तीन घाटों को तैयार कर लिया गया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत अजीमाबाद अंचल में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) ने घाट निर्माण का काम पूरा कर लिया है। बुडको द्वारा भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट को पक्का बनाकर आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। ये तीनों घाट जल्द ही पटना नगर निगम को हैंडओवर कर दिए जाएंगे।

छठ महापर्व में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण किया गया निर्माणः बुडको प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि हर साल छठ महापर्व में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए तीन अतिरिक्त पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। पहले ये घाट कच्चे थे, जिससे श्रद्धालुओं को

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब बुडको ने इनका व्यापक विकास करते हुए पक्के घाटों का निर्माण किया है। सभी घाटों पर सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण के बैरिकेडिंग और उच्च क्षमता वाली प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

भद्र घाट पर विशाल प्रोमिनेड और आधुनिक सुविधाएंः मुख्य रूप से भद्र

> ❑ चेंजिंग रूम, शौचालय और स्नानघर की व्यवस्था

घाट पर 100 मीटर × 40 मीटर क्षेत्र में एक सुसज्जित पक्का घाट बनाया गया है। घाट का चौड़ीकरण कर 565 मीटर लंबा प्रोमिनेड बनाया गया है। वहीं, चेंजिंग रूम, शौचालय और स्नानघर की भी व्यवस्था की गयी है। पूरे क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, जो उच्च क्षमता की प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा महावीर घाट और नौजर घाट पर अतिरिक्त पक्के घाट बनाए गए हैं। महावीर घाट पर 30 मीटर × 20 मीटर आकार के दो नए पक्के घाट बने हैं। वहीं, नौजर घाट पर 30 मीटर × 20 मीटर आकार के दो नए पक्के घाट बनाए गए हैं। इन घाटों पर लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाश, बैरिकेडिंग और स्वच्छता की पूरी व्यवस्था की गई है।

संक्षिप्त समाचार

मालन नदी पर नई विद्युत लाइन का कार्य शुरू, 46 लाख की योजना से मिलेगा स्थायी समाधान हाजी तसलीम अहमद

56 पोल लगाकर 2 किमी लाइन निर्माण-18 हजार उपभोक्ताओं को बारिश में कटौती से राहत

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद, नजीबाबाद। क्षेत्र में विद्युत समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विधायक हाजी तसलीम अहमद द्वारा प्रस्तावित मालन नदी पर नई विद्युत लाइन का कार्य आज विधिवत शुरू करा दिया गया।

इस परियोजना के लिए शासन से 46 लाख रुपये की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी थी। विधायक हाजी तसलीम अहमद ने स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्य का शुभारंभ कराया। इस दौरान अधिशासी अभियंता शैलेन्द्र कुमार, उपखंड अधिकारी प्रथम शम्भूनाथ, उपखंड अधिकारी तृतीय रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट इंजीनियर विनोद उनियाल सहित ठेकेदार भी मौजूद रहे। परियोजना के तहत 56 बड़े विद्युत खंभों के माध्यम से लगभग 2 किलोमीटर लंबी नई विद्युत लाइन बिछाई जाएगी, जिसे आगामी 15 से 20 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नई लाइन के निर्माण से साहनपुर कस्बा, नजीबाबाद के संतोमालन, रमपुरा, वाहिदनगर, बाँसफोड़ान, विजयनगर, मोटाआम सहित कई क्षेत्रों के करीब 18 हजार उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मालन नदी में तेज बहाव के चलते पहले बार-बार विद्युत खंभे बह जाते थे, जिससे कई दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहती थी। अब इस नई व्यवस्था से यह समस्या समाप्त होने की उम्मीद है और विशेषकर बरसात के मौसम में होने वाली बिजली कटौती से लोगों को राहत

नगर पालिका में नवनिर्वाचित सभासदों का सम्मान वहीं शहर में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल

रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से जीते हुए भाजपा की बनी कठपुतली पालिका अध्यक्ष

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। नगर पालिका परिषद रामपुर में नवनिर्वाचित सभासदों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक द्वारा सभासदों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई वार्डों के नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कही गई। लेकिन दूसरी ओर शहर की जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐसे सभासद जो पहले से चुनाव जीतकर आए हैं, उनके वार्डों में न तो नियमित सफाई कराई जा रही है और न ही गलियों व नालियों की मरम्मत या निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।

मंदिरों के आसपास गंदगी और जलभराव-शहर के कई इलाकों में मंदिरों के आसपास पानी भरा हुआ है और गंदगी फैली हुई है। इससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि शहर विधायक के क्षेत्र ज्वाला नगर में भी मंदिर के पास गंदगी और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आई हैं।

वार्ड 8 में सभासद पर सवाल-स्थानीय लोगों ने वार्ड संख्या 8 के सभासद दिनेश कश्यप का नाम लेते हुए कहा कि क्षेत्र में कई गलियां ऐसी हैं जहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।

अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई, कई वाहन जब्त

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में खनिज एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा गोपदबनास, मझौली, मड़वास एवं चुरहट तहसील क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु दिनांक 09.04.2026 एवं 10.04.2026 को दिन एवं रात्रि में सघन जांच अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान ग्राम कुरवाह, तहसील गोपदबनास में प्राप्त शिकायत की जांच में हाइवा क्रमांक MP53HA2238 मुरूम के अवैध उत्खनन/परिवहन में संलिप्त पाया गया। वैधानिक अनुमति/दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर वाहन को नियमानुसार जब्त कर थाना कोतवाली सीधी की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में ग्राम निधिपुरी, तहसील मड़वास स्थित गोपद नदी घाट से रेत का अवैध परिवहन करते हुए बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर (चेसिस क्रमांक MBNAK49ADMTH41575) को जब्त कर थाना मड़वास की अभिरक्षा में सौंपा गया। खनिज कोयले के अनाधिकृत परिवहन में संलिप्त वाहन क्रमांक UP66T7207 एवं UP66T5610 को जब्त कर थाना मझौली में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। साथ ही ग्राम चिलरी, तहसील चुरहट में अवैध रेत परिवहन करते पाए गए ट्रैक्टर क्रमांक MP53ZD3708 एवं हाइवा क्रमांक MP53HA2065 को जब्त कर थाना कमर्जी में अभिरक्षा में रखा गया है। संबंधित वाहन चालकों/स्वामियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिना नंबर वाहनों द्वारा खनिज परिवहन के प्रकरण में संबंधित वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु जिला परिवहन अधिकारी, सीधी को पृथक से लेख प्रेषित किया जाएगा। के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे प्रकरण पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

11अप्रैल को लुरघुटी मे मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

बीएमओ ने हितग्राहियों से लाभ लेने की अपील की

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले के कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर विकेट सिंह ने जानकारी देकर बताया कि जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत लुरघुटी के पंचायत भवन में मेगा शिविर का आयोजन 11अप्रैल को किया गया है। जहां पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु यह शिविर का लगाई जा रही है। इस शिविर मे मेगा हेल्थ कैंप किया जाना है, जिसका उद्देश्य कुसमी के आम जनमानस को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जांच उपचार एवं आयुष्मान कार्ड बनाया जाना व वितरण कार्य ,नेत्र परीक्षण टीवी जांच ,उपचार, किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं एचपीवी वैक्सीनेशन,होना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता हितग्राहियो को लाभ पहुचाने हेतु शिविर लगाई जा रही है। कुसमी खंड चिकित्सा अधिकारी विकट सिंह के द्वारा कहा गया है कि क्षेत्रीय लोग शिविर में पहुंचे, और पहुंचकर इस शिविर का लाभ उठावे इसके साथ साथ कहा है कि कुसमी स्वास्थ विभाग के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है साथ ही बताये की सारी योजनाएं कुसमी पोड़ी भुइमाड टमसार में भी हितग्राहियों को सेवाये दी जा रही है। हर उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर स्वास्थ्य से जुड़े हर मामले का लाभ हितग्राही ले सकते हैं।

न्याय के लिए भटक रही नेत्रहीन मां, शिवसेना ने सौंपा मांग पत्र

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले में एक जन्मजात नेत्रहीन और बेहद गरीब मां को अपने बेटे के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद भी अब तक कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई है। इस मामले को लेकर शिवसेना ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पाण्डेय के अनुसार थाना बाहरी क्षेत्र के ग्राम नकझर निवासी युवक सुधीर पाण्डेय के साथ करीब दो महीने पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया था। इस घटना में युवक के साथ मारपीट कर उसे पैर छूने और अपमानजनक व्यवहार करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। घटना के बाद स्थानीय सांसद राजेश मिश्रा द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता का आश्वासन दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने युवक को मुंबई से बुलाकर नौकरी दिलाने और करीब डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की बात कही थी। लेकिन पीड़ित मां का आरोप है कि पिछले दो महीनों में 6 से 7 बार सांसद कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उनका कहना है कि अब उन्हें सीधे तौर पर मदद देने से मना कर दिया गया। शिवसेना के नगर उपाध्यक्ष विनय त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित मां की तबीयत भी लगातार खराब बनी हुई है। नेत्रहीन होने के कारण उन्हें रोजमर्रा के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय है और वे एक कमरे में जीवन यापन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शिवसेना ने जिला कलेक्टर को सहायता के लिए मांग पत्र सौंपा है। फिलहाल कलेक्टर के दौरे पर होने के कारण पत्र कार्यालय में जमा कर दिया गया है। पार्टी का कहना है कि आगामी जनसुनवाई में पीड़ित मां को स्वयं उपस्थित कराकर हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा 'अर्दली रूम' में समीक्षा: लापरवाही और अनुशासनहीनता पर 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। पुलिस अधीक्षक, कटनी द्वारा आज पुलिस कार्यालय में 'अर्दली रूम' का आयोजन कर विभिन्न पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा विभागीय जांच प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए, एसपी द्वारा कुल 10 प्रकरणों में निम्नानुसार दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की गई है:

प्रमुख दंडात्मक कार्यवाहियां:
वेतन वृद्धि पर रोक: विभागीय जांच में दोषी पाए गए प्रधान आरक्षक/आरक्षक वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर उनकी एक वेतन वृद्धि (असंचयी प्रभाव से) रोकने का दंड दिया गया। बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले थाना स्तर के अधिकारी पर भी समान कार्यवाही की गई।

आर्थिक दंड (जुर्माना):
न्यायालयीन प्रकरणों में विवेचना में देरी करने वाले दो उप-निरीक्षकों (SI) पर 5,000-5,000 का अर्थदंड लगाया गया। विभागीय जांच को अनावश्यक लंबित रखने पर सूबेदार/लाइन पदस्थ अधिकारी पर भी 5,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

गंभीर लापरवाही पर सख्त एक्शन (50% वेतन कटौती):
एक उप-निरीक्षक द्वारा नाबालिग बालिका की दस्तयाबी के मामले में थाना प्रभारी के निर्देशों की अवहेलना करने और वैधानिक कार्यवाही (धारा 161 के कथन एवं वीडियोग्राफी) में विलंब करने एवं वरिष्ठ अधिकारी से अमर्यादित वार्तालाप को गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। संबंधित अधिकारी पर एक माह के वेतन का 50% अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

आगामी नेशनल लोक अदालत 09 मई की तैयारी के लिए न्यायाधीशगण के साथ बैठक आयोजित

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय सीधी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयागलाल दिनकर द्वारा की गई। बैठक में नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक रणनीतियों, लंबित प्रकरणों की पहचान, पक्षकारों की सहमति एवं प्रभावी कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी न्यायालय अपने-अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें लोक अदालत हेतु तैयार करें तथा संबंधित पक्षकारों को समयपूर्व सूचना देकर अधिक से अधिक समझौता योग्य प्रकरणों जैसे- बैंक वसूली प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद तथा अन्य सिविल एवं आपराधिक मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों की सहमति से उनका त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन 26 अप्रैल को जिला जेल सीधी मे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में दिनांक 26 अप्रैल 2026 को जिला जेल सीधी में विशेष जेल लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा। विशेष जेल लोक अदालत के माध्यम से जेल में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के पात्र मामले, जिनमें छोटे अपराध, समझौता योग्य मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले और अन्य उपयुक्त आपराधिक मामले, अपील शामिल हैं, मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाना है। विशेष जेल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा विशेष जेल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर निराकरण करवाने हेतु विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री यतीन्द्र कुमार गुरू, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री दीपक शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विनोद कुमार वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मुकेश कुमार शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मृदुल लटौरिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक, उपस्थित रहे। तहसील न्यायालय चुरहट, मझौली, रामपुर नैकिन के न्यायाधीशगण वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े।

प्रशासन सो रहा है या किसी बड़े हादसे का इंतजार?

- बिना अनुमति दौड़ रहे 'मौत के झूले', कभी भी जा सकती है कई जिंदगियां
- युवक गंभीर घायल, फिर भी जिम्मेदार खामोश-मेले बने हादसों के अड्डे

लोकतंत्र की शान, खिज़र अहमद

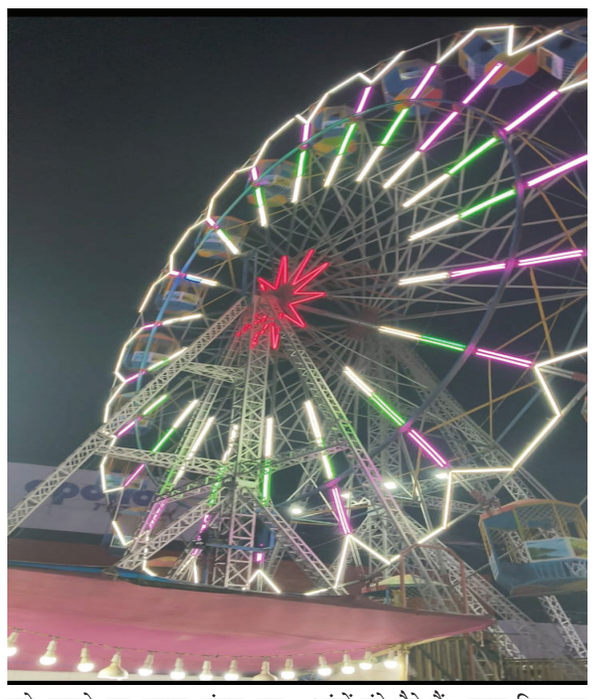

नजीबाबाद। शहर में इन दिनों लग रहे नुमाइश मेले अब मनोरंजन नहीं बल्कि खुलेआम मौत का खेल बनते जा रहे हैं। रायपुर रोड स्थित मेले में झूले से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मौन बनी हुई है। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि इन मेलों में चल रहे बड़े-बड़े झूले बिना अनुमति, बिना फिटनेस जांच और बिना किसी सुरक्षा मानक के संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में हर पल किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। साफ दिख रहा है कि न पुलिस की मौजूदगी है, न प्रशासन का नियंत्रण। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी बड़े झूले को चलाने से पहले तकनीकी जांच, फिटनेस सर्टिफिकेट और विभागीय अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन यहां खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सबसे बड़ा सवाल: क्या प्रशासन किसी मौत का इंतजार कर रहा है?

शहर की प्रदर्शनियों में पहले ही लाठी-डंडे चलने और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बावजूद न तो सुरक्षा बढ़ाई गई, न ही अवैध संचालन पर रोक लगाई गई। मेले में दिनभर अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं और परिवारों ने मेले में जाना कम कर दिया है। छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणियां और अव्यवस्था अब आम बात हो चुकी है।

देवरी हटाई मंडल में आयोजित हुआ पंडित दीन दयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी: बड़वारा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के बड़वारा देवरी हटाई मंडल प्रशिक्षण वर्ग पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पधारे आप सभी को देवरी हटाई मंडल की ओर से बहुत ,बहुत आभार कार्यक्रम की पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जब प्रारंभ हुआ तो प्रशिक्षण कार्यशाला में लहराते ध्वजों एवं शान्त वातावरण ने सबका मन मोह लिया इस शुरुआत की कड़ी में बड़वारा विधानसभा के लोकप्रिय लाडले विधायक श्री धीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने पार्टी ध्वजा रोहण कर मंत्रोच्चरण के शुभ आरंभ किया एवं आपके नेतृत्व में सफ़ल हुआ और प्रथम सत्र में आपने सरकार की उपलब्धियों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया प्रशिक्षण वर्ग में 8 सत्र चले जिसमें द्वितीय सत्र माननीय विधानसभा प्रभारी विजय गुप्ता जी तृतीय सत्र मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष सुनील उपाध्याय जी चतुर्थ सत्र सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम जी पंचम सत्र माननीय जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी सष्टम सत्र मन की बात की प्रभारी रवि खरे जी सप्तम सत्र ललित जायसवाल जी अष्टम सत्र द्वितीय दिवस जिला मंत्री आशीष गुप्ता जी की प्रखर वक्ता एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ से पधारे वरिष्ठ ,जनप्रतिनिधि जन,मंडल पदाधिकारी, मातृशक्ति , बुथ अध्यक्ष सभी ने अपनी सहभागिता निभाई एवं इस प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाया एवं पधारे आप सभी देवतुल लकार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार एक नया इतिहास रचने के लिए

मुनाफाखोरों और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा जानबूझकर कर रही है गेहूं खरीदी में देरी- प्रदीप सिंह दीपू

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

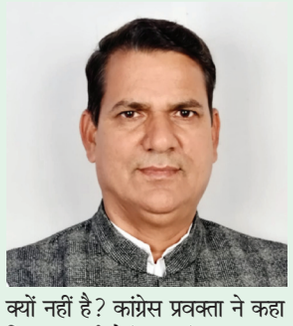

सीधी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने जारी एक बयान में कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के किसानों को पूरी तरह से बिचौलियों एवं मुनाफाखोर दलालों के हाथ लूटने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सुनियोजित साजिश के तहत गेहूं खरीदी में जानबूझकर इसलिए विलंब कर रहे हैं ताकि भाजपा से जुड़े दलाल मुनाफाखोर और बिचौलिए औने-पौने दाम पर गेहूं खरीद कर किसानों के खून पसीने की कमाई पर डाका डाल सके। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार तीन बार गेहूं खरीदी का डेट बढ़ाकर अपने किसान विरोधी नीति और नियति का परिचय दे चुकी है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बरदाने के संकट का बहाना बनाकर खरीदी चालू करने में विलंब किया जा रहा है। जबकि बारदाने का देश में कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ उत्पादक देशों की श्रेणी में आता है। भारत में वरदानों का आयात खाड़ी देशू से नहीं होता खाड़ी देशों से केवल क्रूड ऑयल और एलपीजी का आयात होता है। बारदानों का नही। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में भाजपा से जुड़े हुए मुनाफाखोर बिचौलिए जो किसानों की फसल औने-पौने दाम पर खरीद रहे हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना है, लेकिन सरकार के पास क्यों नहीं है? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है। लगभग 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन के हिसाब से 160 लाख मेट्रिक टन गेहूं बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन किसान विरोधी प्रदेश की भाजपा सरकार ने मात्र 78 लाख मेट्रिक टन की खरीदी का टारगेट बनाकर किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वास घात किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के किसानों का 82 लाख मैट्रिक टन गेहूं बिचौलियों और दलालों के माध्यम से भाजपाइयों के गोदाम में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बैरसिया के भाजपा विधायक विष्णु खत्री के गोदाम में हजारों टन गेहूं पकड़ा जा चुका है। आखिर जब प्रदेश में बारदाना की कमी है तो यह भाजपा के भ्रष्ट नेता और दलालों के पास वारदाने कहां से आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में लगभग 20 करोड़ बारदाने की जरूरत थी लेकिन प्रदेश की किसान विरोधी बीजेपी की सरकार ने केंद्र सरकार से केवल दो करोड़ 60 लाख बारदाने का ही आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वारदाने का संकट युद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के षड्यंत्र के वजह से हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2023 विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी के नाम से गेहूं पर 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन केवल 40 बोनस देकर किसानों के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 150 रुपए बोनस मिल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर गेहूं खरीदी में विलंब किया जा रहा है ताकि प्रदेश के किसान बिचौलियों और दलालों के हाथ औने पौने दाम में अपनी उपज बेचने को मजबूर हो जाए और सरकार गेहूं खरीदने और समर्थन मूल्य देने की जिम्मेदारी से बच सके।

संक्षिप्त समाचार

पार्टी अध्यक्ष का निर्देश- नेपाल में सत्तारूढ़ दल के सांसद अनावश्यक न जाएं मंत्रालय

काठमांडू। नेपाल की सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने शुक्रवार को पार्टी के सांसदों और नेताओं को सख्त निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत हित या राजनीतिक लॉबिंग के लिए सिंहदरबार स्थित सरकारी मंत्रालयों में अनावश्यक जाना बंद करें। आरएसपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए लामिछाने ने सांसदों को रिश्तेदारों और सहयोगियों के लिए नियुक्ति या सुविधा मांगने से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का सत्ता तक पहुंचना "जेन-जी" मतदाताओं के बलिदान का परिणाम है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को पारंपरिक भाई-भतीजावाद, नातावाद कृपावाद में शामिल होने के बजाय उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा के अनुसार आरएसपी ने शिकायत निवारण को संस्थागत बनाने के लिए एक नया ड्यूटी कैलेंडर लागू किया है। इसके तहत हर दिन एक केंद्रीय समिति सदस्य और एक सांसद पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगे, ताकि आम जनता की समस्याओं को सुना जा सके और मंत्रालयों में भीड़ कम की जा सके। झा ने कहा कि सांसदों और मंत्रियों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं।" संसदीय सत्र के स्थगन के साथ ही लामिछाने ने सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटकर स्थानीय समन्वय और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश भी दिया है।

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश -रविवार को ओपीडी का करे संचालन

काठमांडू। नेपाल सरकार ने देशभर के अस्पतालों में रविवार को भी बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवा संचालित करने का निर्देश दिया है। सप्ताह में दो दिन अवकाश देने के सरकारी निर्णय के बाद रविवार को अस्पताल सुनसान होने लगे थे, जिसके बाद मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। दो दिन के साप्ताहिक अवकाश के निर्णय के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों ने रविवार को ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं। लेकिन दूर-दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रविवार को अस्पताल पहुंचकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। जनस्तर पर तीखी आलोचना होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीच का रास्ता अपनाया है। मंत्रालय के सह-प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, "कार्यभार और उपलब्ध जनशक्ति का प्रबंधन करते हुए रविवार को भी अनिवार्य रूप से ओपीडी सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।" मंत्रालय ने अस्पताल प्रशासन को कुछ विकल्प भी दिए हैं, जिनमें रविवार को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों या चिकित्सकों को शनिवार के अलावा सप्ताह के किसी अन्य दिन बदले में छुट्टी देने की व्यवस्था करने को कहा गया है। मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट के अनुसार डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था केवल संघीय अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सभी सातों प्रदेशों के प्रादेशिक अस्पतालों में भी अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी।

नासिक की आईटी-कंपनी में लड़कियों के यौन शोषण-धर्मांतरण का मामला, 6 मुस्लिम टीम लीडर

नासिक। नासिक की मल्टीनेशनल IT कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन शोषण और ऑफिस में जबरन नमाज पढ़ने, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मुस्लिम टीम लीडर्स और HR मैनेजर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कंपनी कैंपस में घुसकर हंगामा किया। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले चार साल के दौरान HR मैनेजर से शिकायत की गई, लेकिन हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। मामला तब सामने आया, जब कुछ महिला कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव देखा गया। उन्होंने रमजान में रोजा रखा। अपनी पुरानी आदतें और परंपराएं छोड़ दीं। अपनी जीवनशैली बदल ली और सहेलियों से भी दूरी बना ली। लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया। उसका व्यवहार भी बदल गया। शुरू में पीड़ित लड़कियां डर और समाज के दबाव के कारण चुप थीं, लेकिन बाद में 9 लड़कियों और एक युवक ने पुलिस में शिकायत की, तब यह मामला सामने आया। अगर कोई लड़की काम पर नहीं आती थी, तो आरोपी उसके घरवालों से संपर्क करने की कोशिश करते थे। इस मामले में कंपनी के कुछ बड़े पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों का भी नाम सामने आया है।

एमपी-यूपी में तापमान 6° से 10° तक बढ़ सकता है

भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून। मध्य प्रदेश में आज से बारिश का असर कम रहेगा। इसके साथ ही दिन का तापमान 4°C से 6°C तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं है। बीते दो दिन में 50 से ज्यादा जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का असर रहा। राज्य का तापमान 10°C तक बढ़ सकता है। राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर थमने के साथ तापमान बढ़ने लगा है। अगले 2 सप्ताह में गर्मी तेज होने के साथ कुछ शहरों का तापमान 40°C या उससे ऊपर जा सकता है। देश के अरुणाचल प्रदेश, असम समेत 9 राज्यों में बारिश-आंधी की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में अब तक सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हो चुकी है। आमतौर पर 2-9 अप्रैल के बीच 17.6mm बारिश होती थी, इस बार 52.6mm हुई। राज्य के अधिकतम तापमान में भी 6.4°C की कमी आई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ियों पर बर्फबारी हो सकती है। इधर, आंध्र प्रदेश में अगले पांच दिन तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने के साथ गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा।

हिमाचल में मणिमहेश यात्रा पर प्रतिबंधःपरिक्रमा स्थल पर पुलिस की तैनाती, विशेष निगरानी के आदेश

भरमौर, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 'मणिमहेश यात्रा' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। SDM भरमौर ने पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए कि परिक्रमा स्थल धंछो, गौरीकुंड और मणिमहेश में पुलिस जवानों की तैनाती कर विशेष निगरानी शुरू की जाए। किसी भी यात्री को धंछो से आगे न जाने दिया जाए। कुछ यात्री प्रशासन को सूचित किए बगैर चोरी-छिपे मणिमहेश जाने लगे हैं, जबकि भरमौर में अभी चार-पांच फीट से भी ज्यादा बर्फ है। दो दिन पहले भी यहां ताजा हिमपात हुआ है। मणिमहेश जाने वाले रास्ते 2025 की भारी बरसात और बादल फटने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में मणिमहेश की यात्रा जानलेवा साबित हो सकती है। SDM भरमौर ने अपने आदेशों में कहा कि 'कार्तिक स्वामी मंदिर' के कपाट 14 अप्रैल को खुल रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी कुछ भक्त अभी से कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने लगे हैं। इस दौरान कुछ लोग मणिमहेश की ओर जा रहे हैं। किसी को भी परिक्रमा मार्ग (धंछो, गौरीकुंड और मणिमहेश) पर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। SDM ने निर्देश दिए कि हडसर मेन गेट पर वाहनों की नियमित जांच की जाए। साथ ही, मणिमहेश जाने वाले श्रद्धालुओं को परिक्रमा मार्ग पर जाने से रोका जाए और उन्हें मार्ग की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के रवैये की आलोचना की

एजेंसी, इस्तांबुल

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरीने ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर तीखी आलोचना की है। उन्होंने मौजूदा सीज़फ़ायर को "बेहद ढीला-ढाला" बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हालात आगे चलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। पूर्व विदेश मंत्री ने विशेष रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य की अनिश्चित स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह संकट अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की ओर धकेलते रहे हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन ने ऐसे प्रस्तावों को पहले ठुकरा दिया था।

तुर्किए की सरकारी समाचार सेवा अनाडोलू एजेंसी (एए) ने बोस्टन पब्लिक रेडियो पर दिए एक इंटरव्यू के हवाले से बताया कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बड़े वैश्विक और आर्थिक नतीजों को जन्म दे सकता है। उन्होंने मौजूदा नाजुक सीजफायर पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने मौजूदा दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर पर सवाल उठाते हुए इसे "बेहद ढीला-ढाला" बताया। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी, जो एक पूर्व सीनेटर भी हैं और साल 2015 में उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते में बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। हिलेरी क्लिंटन के बाद, केरी ने 2013 से 2017 तक ओबामा के कार्यकाल में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया।

उन्होंने बड़े नतीजों की चेतावनी देते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे यह आगे बढ़ेगा यह और भी गंभीर और खतरनाक होता जाएगा। होर्मुज जलडमरूमध्य अब ईरान के नियंत्रण में है, जो युद्ध शुरू होने से पहले उनके नियंत्रण में नहीं था। पूर्व विदेश मंत्री ने आगे कहा कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने वाले अगले कदमों से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को होने वाले खतरे के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका आर्थिक असर इतना बड़ा और जटिल हो सकता है, जितना हमने पहले कभी नहीं झेला।

वैश्विक तेल परिवहन के एक अहम रास्ते, होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र करते हुए जॉन केरी ने सीजफ़ायर के पालन को लेकर अनिश्चितता जताई। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक, जब से यह संघर्ष-विराम शुरू हुआ है, तब से तेल टैंकरों की आवाजाही सीमित ही रही है। जॉन केरी ने तर्क दिया कि ट्रंप इस संघर्ष को शुरू करने के लिए किसी के प्रभाव में आ गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में, यह एक ऐसा युद्ध है जो असल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस पुराने सपने को पूरा कर रहा है, जिसके तहत वह ईरान को उतना नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जितना उन्हें करने की इजाजत मिलती। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को सैन्य कार्रवाई की ओर मोड़ा। नेतन्याहू ने पहले भी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और बराक ओबामा से ईरान पर इसी तरह के हमले करने का आग्रह किया था लेकिन उन दोनों ने ही इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और तनाव बढ़ाने से इनकार कर दिया था। केरी ने इस बात को भी दोहराया कि इस संघर्ष से पहले ईरान से कोई तत्काल खतरा नहीं था। उन्होंने ईरान की क्षमताओं को सीमित रखने का श्रेय कुछ हद तक 2015 की परमाणु संधि को दिया।

114 नए राफेल स्वदेशी मिसाइलों से लैस होंगे, 18 जेट फ्रांस से आएंगे

96 भारत में बनेंगे, सोर्स कोड नहीं मिलेगा

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। इन जेट्स को स्वदेशी मिसाइलों और हथियार सिस्टम से लैस किया जाएगा। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, डील में इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट (ICD) शामिल किया जाएगा। इसके जरिए तय होगा कि राफेल जेट और स्वदेशी हथियार आपस में कैसे जुड़ेंगे और साथ काम करेंगे। रक्षा मंत्रालय अगले महीने राफेल फाइटर जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी करेगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू होगी। इस सौदे को फेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने 12 फरवरी को मंजूरी दी थी। 114 में से 18 राफेल जेट्स फ्रांस से फ्लाई-अवे कंडीशन में मिलेंगे। बाकी 96 जेट्स भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें 25% कलपुर्जे स्वदेशी होंगे।

फ्रांस सोर्स कोड शेयर नहीं करेगाः रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ्रांस सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, कोई भी देश अपने फाइटर जेट का सोर्स कोड साझा नहीं करता। यही कोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टारगेट ट्रैकिंग और हथियार सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे साझा नहीं किया जाता। हालांकि, डील पर इसका असर नहीं है।

दावा- रूस और अमेरिका भी नहीं देते सोर्स कोडः एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को रूस ने 5th जनरेशन Su-57 फाइटर जेट के दो स्क्वाड्रन देने की पेशकश की है। वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ मिलकर Su-30 MKI जेट्स को अपग्रेड भी कर रहा है। हालांकि रूस ने इन दोनों फाइटर जेट्स के सोर्स कोड कभी शेयर नहीं किए। अमेरिका का भी यही रुख है। भारत के पास मौजूद अमेरिकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर से जुड़े सॉफ्टवेयर कोड भी शेयर नहीं किए जाते।

ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान रवाना

एजेंसी, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

ईरान के साथ अहम बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। रवाना होते वक्त उन्होंने कहा कि ईरान ईमानदारी से बातचीत करे और कोई 'खेल' न खेले।

वेंस ने कहा कि अगर तेहरान गुड फेथ में बात करेगा, तो अमेरिका भी खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अगर वह चालाकी करने की कोशिश करता है, तो अमेरिकी टीम सख्त रुख अपनाएगी।

इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बैठक होने वाली है। लेकिन बैठक से पहले ही अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि ईरानी डेलिगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान लेबनान में जारी इजराइली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

❐ कहा- ईरान खेल न खेले, ईमानदारी से बात करे, अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा ईरानी डेलीगेशन

इससे पहले खबर आई थी कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इन दावों को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी थी।

मप्र में महिला उद्यमिता को मिला बढ़ावा, एमएसएमई में 17 फीसद इकाइयों को महिलाएं कर रहीं संचालित

एजेंसी, भोपाल

◆ एमएसएमई विकास नीति : 2025 ने महिलाओं को बनाया आत्म निर्भर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तीकरण, उद्यमिता और वोकल फॉर लोकल' के संकल्प को मध्य प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से साकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अगुवाई में एमएसएमई विकास नीति : 2025 और स्टार्ट-अप नीति : 2025 ने महिलाओं को उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब एमएसएमई सेक्टर की 17 फीसद इकाइयों को महिलाएं संचालित कर रही हैं।

मध्य प्रदेश की नीतियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और योजनाओं के कारण ही 24 लाख 34 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में से 4.11 लाख यानि 17 फीसदी इकाइयां महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं। गत वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पित स्टार्ट-अप नीति में 7264 में से 3476 यानि 48 स्टार्ट-अप महिलाओं के हैं। मध्यप्रदेश की यह तस्वीर राज्य सरकार की देश में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराता है। इससे स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत का सपना मध्यप्रदेश में साकार हो रहा है।

जनसंपर्क अधिकारी राजेश बैन ने शुक्रवार को बताया कि ने बताया कि मध्य प्रदेश की एमएसएमई विकास नीति : 2025 में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब उन महिला उद्यमियों को जो संयंत्र और मशीनरी में निवेश कर रही हैं, उन्हें 10 करोड़ तक के निवेश पर अधिकतम 48 प्रतिशत तक की पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए यह दर अधिकतम 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत है। इस नीति से मार्च 2026 तक 24.34 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में से करीब 4.11 लाख महिलाओं द्वारा स्थापित की गई हैं।

मुंबई एयरपोर्ट पर 38 करोड़ का 29.37 किलो सोना जब्त

◆ 24 केन्याई महिलाएं गिरफ्तार, कपड़ों-बैग में छिपाकर ला रही थीं

एजेंसी, मुंबई

मुंबई एयरपोर्ट पर बुधवार को 29.37 किलो सोने के साथ 24 केन्याई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने इनसे 37.74 करोड़ का सोना जब्त किया है। महिलाएं सोना कपड़ों और बैग में छिपाकर ला रही थीं। DRI को इनपुट मिला था कि केन्या के नैरोबी से आने वाली कुछ महिला यात्री सोना लेकर मुंबई पहुंचेंगी। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 'धहाबू ब्लिट्ज' ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध यात्रियों को रोका गया।

जांच में महिलाओं के पास से 29.37 किलो सोना बरामद हुआ। इसमें 25.10 किलो सोने की सिल्लियां और 4.27 किलो जेवर शामिल हैं।

ट्रेनिंग देकर तस्करी कराई जा रही थीः एजेंसी के मुताबिक, महिलाओं को सोना छिपाने और एयरपोर्ट जांच से बचने के तरीके सिखाए गए थे। इससे साफ है कि काम एक संगठित नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था, जो कैरियर्स के माध्यम से सोना भारत भेज रहा था। गिरोह खुद सोना नहीं लाता था, बल्कि पैसों के लालच में लोगों को कैरियर बनाकर तस्करी कराता था।

यह इस साल मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़े गए सबसे बड़े मामलों में से एक है। सभी महिलाओं को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एजेंसी अब इस नेटवर्क के सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस ऑपरेशन का नाम 'धहाबू ब्लिट्ज' रखा गया है। 'धहाबू' स्वाहिली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ सोना होता है।

यूपी एसआईआर फाइनल लिस्ट में 2.04 करोड़ नाम कटे

एजेंसी, लखनऊ

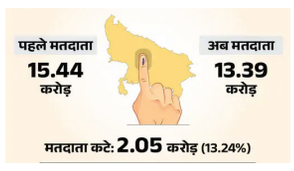

◆ डिप्टी सीएम पाठक की सीट पर 34% वोटर कम हुए

यूपी में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की फाइनल लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी। यूपी में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13.39 करोड़ हो गई है। फाइनल लिस्ट में 2.04 करोड़ नाम कटे हैं। SIR से पहले अक्टूबर 2025 में यूपी में कुल 15.44 करोड़ वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 12.55 करोड़ हो गया था। इसमें 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो नाम कटे थे, उसमें 84 लाख नामों को फाइनल लिस्ट में जोड़ा गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया- लखनऊ में सबसे ज्यादा 9.14 लाख मतदाता कम हुए हैं। प्रयागराज में 8.26 लाख, कानपुर नगर में 6.87 लाख, आगरा में 6.37 लाख और गाजियाबाद में 5.74 लाख मतदाता कम हुए हैं। प्रतिशत के लिहाज से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 34.18% वोटर कम हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो आईटी मंत्री सुनील शर्मा की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 3,16,484 मतदाता कम हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा सबसे अधिक मतों से जीते थे।

अंतिम सूची voters.eci.gov.in और ceouttarpradesh.nic.in पर देखी जा सकती है। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए किया जा सकता है।

लखनऊ में सबसे ज्यादा 9.14 लाख नाम कटेः सबसे ज्यादा 22.89% वोटर्स के नाम लखनऊ जिले में कटे। SIR से पहले राजधानी में 39,94,535 वोटर थे। ड्राफ्ट सूची में 27,94,397 नाम रह गए। अंतिम सूची में 2,85,961 नाम बढ़े। इस हिसाब से यहां कुल 9,14,177 नाम कटे हैं। अब कुल 30,80,358 मतदाता रह गए हैं। प्रयागराज जिला दूसरे नंबर पर है। SIR से पहले यहां 46,92,860 मतदाता थे। ड्राफ्ट सूची में 11,56,306 नाम कट गए और मतदाता 35,36,554 रह गए।

11 साल बाद जेल से बाहर आया रामपाल

एजेंसी, हिसार/ सोनीपत

हरियाणा में हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहा रामपाल शुक्रवार को 11 साल और 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल-2 से निकला। परिवार के लोग उसे लेने के लिए जेल पहुंचे थे। जेल के गेट से रामपाल मुस्कुराता हुआ निकला। इस दौरान गेट पर तैनात एक पुलिस कर्मचारी ने रामपाल के सामने हाथ जोड़े। इसके बाद वह सफेद पर्दे लगी फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल गया।

रामपाल हिसार से सीधा सोनीपत जिले के गोहाना में स्थित धनाना के सतलोक आश्रम के लिए रवाना हुआ। उसके काफिले में डिफेंडर, फॉर्च्यूनर जैसी 20 गाड़ियां हैं। हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी काफिले को एस्कॉर्ट कर रही है। धनाना गांव में रामपाल के समर्थक जुटे हुए हैं। रामपाल के भतीजे युद्धवीर ने बताया कि गांव से एक किलोमीटर पहले ही रामपाल का स्वागत किया जाएगा। आज का दिन उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। 8 अप्रैल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को जमानत मंजूर की थी। आज सुबह ही कोर्ट के आदेश पर रामपाल के वकीलों ने हत्या के दो मामलों में 5-5 लाख के बेल बॉन्ड जमा करवाए। नवंबर 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को एक केस में कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी, प्रदेश में कुल 13.39 करोड़ मतदाता, 84 लाख मतदाताओं की हुई वृद्धि

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। इसमें 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है।

इनमें प्रदेश में पुरुष मतदाता 7 करोड़, 30 लाख, 71 हजार 61 और महिला मतदाता 6 करोड़, नौ लाख, 9525 है। एसआईआर में विभिन्न कारणों से 8 लाख 15 हजार 996 मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। इनमें नोटिस देने के बावजूद सही जवाब न मिलने के कारण काटे गये 3 लाख 50 हजार 436 मतदाताओं के भी नाम शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता में बताया कि प्रदेश में 166 दिन तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। जारी मतदाता सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता हैं। इसमें 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। इनमें प्रदेश में पुरुष मतदाता 7 करोड़, 30 लाख, 71 हजार 61 और महिला मतदाता 6 करोड़, नौ लाख, 9525 है। तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4 हजार 206 है। प्रदेश में 18 से 19 आयुवर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 17 लाख, 63 हजार 360 है। इसमें मतदाताओं में 54.54 प्रतिशत पुरुष जबकि 45.46 प्रतिशत महिला मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वे मतदाता अभी भी फॉर्म 6 भरकर सूची में शामिल हो सकते हैं।

लखनऊ समेत पांच जिलों में मतदाताओं की सर्वाधिक वृद्धि हुईः मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज जारी की गयी अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश के पांच जिलों में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इनमें प्रयागराज टॉप पर है। प्रयागराज में 3 लाख 29 हजार 421 मतदाता, लखनऊ में 2 लाख, 85 हजार 961 मतदाता, बरेली में 2 लाख 57 हजार 920 मतदाता, गाजियाबाद में 2 लाख 43 हजार 666 मतदाता और जौनपुर में 2 लाख 37 हजार 590 मतदाता बढ़े हैं। इसके अलावा प्रदेश के जिन पांच विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदाता वृद्धि दर्ज की गयी है। उनमें साहिबाद में 82 हजार,जौनपुर में 56 हजार 158 ,लखनऊ पश्चिम में 54 हजार 822,फिरोजाबाद में 47 हजार 557 मतदाता बढ़े हैं।

भारत की जनगणना 2027- सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जातिगत विषय रोकनें जनहित याचिका खारिज -डेटा क्रांति,सामाजिक यथार्थ और संवैधानिक बहस का संगम भारत का निर्णायक मोड़-समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

NA20200930

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» ज़नगणना 2027- सामाजिक संरचना, राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीतियों के लिए निर्णायक मोड़ साबित होगी

» ज़नगणना 2027 प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार- डिजिटल तकनीक, जातिगत डेटा और विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से यह जनगणना देश की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करेगी -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत जैसे विशाल और विविधता पूर्ण देश में जनगणना केवल आबादी की गिनती नहीं होती,बल्कि यह शासन,विकास और सामाजिक न्याय का आधारभूत स्तंभ होती है। लगभग 146.2 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि संवैधानिक और प्रशासनिक परंपरा के अनुसार हर 10 वर्षों में जनगणना कराई जानी चाहिए थी। इस दृष्टि से 2021 में जनगणना होना तय था, किंतु यह प्रक्रिया कई कारणों से स्थगित होती रही। अब 2027 की प्रस्तावित जनगणना न केवल इस लंबित प्रक्रिया को पूरा करेगी, बल्कि यह भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत भी मानी जा रही है। यह पहली बार होगा जब देश पूरी तरह डिजिटल जनगणना करेगा और 1931 के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि इस प्रकार यह जनगणना केवल एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं,बल्कि सामाजिक संरचना,राजनीतिक विमर्श और आर्थिक नीतियों के लिए निर्णायक मोड़ साबित होगी।जातिगत जनगणना को लेकर दायर याचिकाओं पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 10 अप्रैल 2026 को एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को रोकने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई और इसे न्यायिक मर्यादा के खिलाफ बताया। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है,बल्कि यह भी संकेत देता है किसरकार की नीतिगत प्रक्रियाओं में न्यायपालिका अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहती है, जब तक कि कोई स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन न हो।इससे पहले भी फरवरी 2026 में अदालत ने जातिगत डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका इस विषय को नीतिगत क्षेत्र का हिस्सा मानते हुए सरकार को आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। साथियों बात अगर हम 2021 की जनगणना क्यों टलीः महामारी से प्रशासनिक जटिलताओं तक इसको समझने की करें तो,2021 की जनगणना के स्थगन के पीछे सबसे प्रमुख कारण वैश्विक महामारी कोविड -19 थी, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की प्रशासनिक गतिविधियों को प्रभावित किया। भारत में मार्च 2020 से लागू लॉकडाउन,सामाजिक दूरी के नियम और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के चलते घर-घर जाकर डेटा संग्रह करना लगभग असंभव हो गया था। इसके अलावा, महामारी के दौरान सरकारी संसाधनों और मानवशक्ति का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं और राहत कार्यों में लगा हुआ था, जिससे जनगणना जैसी व्यापक प्रक्रिया को प्राथमिकता देना कठिन हो गया।इसके अतिरिक्त, तकनीकी तैयारी और डिजिटल अवसंरचना के विकास में भी अपेक्षित समय लगा।चूंकि सरकार इस बारजनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाना चाहती थी,इसलिए मोबाइल एप्लिकेशन, डेटा सुरक्षा, सर्वर क्षमता और प्रशिक्षण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान देना पड़ा। इस प्रकार महामारी के साथ-साथ प्रशासनिक और तकनीकी कारणों ने मिलकर 2021 की जनगणना को टाल दिया,जो अब 2027 में सटिकाता से आयोजित की जा रही है। साथियों बात अगर हम डिजिटल जनगणना 2027ः डेटा संग्रहण की नई क्रांति को समझने की करें तो 2027 की जनगणना को भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रक्रिया मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन पोर्टल और रियल- टाइम डेटा संग्रहण तकनीकों के माध्यम से संचालित होगी। इसमें जियो-टैगिंग,स्व-गणना और डेटा का तत्काल सत्यापन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।इस डिजिटल परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि डेटा संग्रहण अधिक सटीक, तेज और पारदर्शी होगा। पहले जहां आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करने में वर्षों लग जाते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया काफी हद तक त्वरित हो सकेगी। साथ ही, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सरकार नीतियों को अधिक प्रभावी और लक्षित बना सकेगी।हालांकि, इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे भी सामने आते हैं। इतनी बड़ी आबादी का संवेदनशील डेटा डिजिटल रूप में संग्रहित करना साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होगा। अतः सरकार को इस दिशा में मजबूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने होंगे।

साथियों बात अगर हम जातिगत जनगणनाः1931 के बाद एक ऐतिहासिक पहल को समझने की करें तो भारत में 1931 के बाद से व्यापक जातिगत जनगणना नहीं की गई थी। स्वतंत्रता के बाद केवल अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े ही एकत्र किए जाते रहे। लेकिन 2027 की जनगणना में सभी जातियों का डेटा एकत्र करने की योजना है, जो इसे ऐतिहासिक बनाती है।जातिगत जनगणना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से सरकार यह समझ सकेगी कि विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या है और किन समूहों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। यह डेटा आरक्षण नीति, कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा।हालांकि,इस पहल के साथ कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। आलोचकों का मानना है कि जातिगत आंकड़े समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं और पहचान की राजनीति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहीं समर्थकों का तर्क है कि बिना सटीक डेटा के सामाजिक न्याय की नीति बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहन बहस का विषय बना हुआ है। साथियों बात अगर हम जनगणना की संरचनाःदो चरणों में विस्तृत प्रक्रिया को समझने की करें तो जनगणना 2027 को दो मुख्य चरणों में आयोजित किया जाएगा।पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हाउस लिस्टिंग और आवास गणना का होगा,जिसमें घरों की स्थिति,उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण एकत्र किया जाएगा।इसमें जियो- टैगिंग के माध्यम से प्रत्येक आवास का स्थान भी दर्ज किया जाएगा।दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना का होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आयु,लिंग,शिक्षा,रोजगार और जाति से संबंधित डेटा एकत्र किया जाएगा। इसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है,अर्थात इस समय तक जन्मे सभी व्यक्तियों को जनगणना में शामिल किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्रों,जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमालयी राज्यों में, मौसम और भौगोलिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अलग संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। साथियों बात अगर हम 33 सवालों की सूचीःजीवनशैली और विकास का समग्र आकलन को समझने की करें तो इस बार जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवाल केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं होंगे,बल्कि वे लोगों की जीवनशैली, आर्थिक स्थिति और तकनीकी पहुंच का भी आकलन करेंगे।इसमें पीने के पानी,बिजली,शौचालय, ईंधन, इंटरनेट,मोबाइल,कंप्यूटर और वाहन जैसी सुविधाओं से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे।पहली बार यह भी पूछा जाएगा कि परिवार के पास चार पहिया वाहन है या नहीं, और वे कौन-सा प्रमुख अनाज उपभोग करते हैं।इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार देश की बदलती उपभोक्ता प्रवृत्तियों और जीवन स्तर को समझ सकेगी।यह डेटा कृषि नीति, डिजिटल इंडिया, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। इस प्रकार जनगणना अब केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि विकास की दिशा तय करने वाला उपकरण बन चुकी है। साथियों बात कर हम आर्थिक और नीतिगत प्रभावः डेटा से विकास की दिशा को समझने की करें तो जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं।शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती हैं।2027 की जनगणना से प्राप्त डेटा अगले 10 वर्षों की विकास योजनाओं को दिशा देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच कम पाई जाती है, तो वहां डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी विशेष समुदाय की आर्थिक स्थिति कमजोर पाई जाती है, तो उनके लिए लक्षित योजनाएं बनाई जा सकती हैं।इस प्रकार यह जनगणना भारत की आर्थिक रणनीति और सामाजिक नीति के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी। साथियों बात अगर हम सामाजिक और राजनीतिक प्रभावः पहचान, प्रतिनिधित्व और संतुलन के दृष्टिकोण से समझने की करें तो जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इससे विभिन्न समुदायों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आएगा,जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण नीति को प्रभावित कर सकता है।हालांकि, इसके साथ पहचान की राजनीति के बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। विभिन्न जातियां अपने अधिकारों और हिस्सेदारी के लिए अधिक मुखर हो सकती हैं, जिससे सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है।इसलिए सरकार और समाज दोनों के लिए यह आवश्यक होगा कि इस डेटा का उपयोग संतुलित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए, ताकि यह सामाजिक समरसता को बनाए रखते हुए विकास को बढ़ावा दे सके। साथियों बात अगर हम भारतीय जनसंख्या गणना2027 को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः भारत का वैश्विक उदाहरण इस रूप में समझने की करें तो विश्व के कई देशों में जनगणना की प्रक्रिया नियमित रूप से होती है, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में इसे सफलता पूर्वक आयोजित करना एक बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल जनगणना और व्यापक सामाजिक डेटा संग्रहण के माध्यम से भारत एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर सकता है।यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है, तो यह अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण और नीति निर्माण किया जा सकता है। अतः ग्राम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि भविष्य की दिशा तय करने वाला ऐतिहासिक कदम हैं,जनगणना 2027 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का आधार है। डिजिटल तकनीक, जातिगत डेटा और विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से यह जनगणना देश की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करेगी।हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां और विवाद भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि इसे पारदर्शिता, संवेदनशीलता और संतुलन के साथ लागू किया जाए, तो यह भारत के विकास को नई दिशा दे सकती है। इसलिए यह जनगणना केवल वर्तमान का आकलन नहीं, बल्कि भविष्य की योजना है एक ऐसा भविष्य जिसमें डेटा के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे और विकास की प्रक्रिया अधिक समावेशी और प्रभावी

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

मोहन का मिशन कृषक कल्याण : किसानों की समृद्धि, एमपी की प्रगति

लेखक - हर्षवर्धन पान्डे

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की देन 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की ऐतिहासिक घोषणा है। यह मिशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसान परिवारों के जीवन को संवारने, उनकी आय दोगुनी करने और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक विजनरी संकल्प है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के उत्थान को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए धरातल पर उन्होनें कई ठोस कदम उठाए हैं। डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की किसान-केंद्रित नीतियां व्यावहारिक और दूरदर्शी हैं। डॉ. मोहन यादव सरकार ने मिशन ज्ञान के अंतर्गत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी है। अप्रैल 2025 में कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन को मंजूरी दी जिसका मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना , जलवायु-अनुकूल और सतत कृषि को बढ़ावा देना जैविक खेती, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना है। खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ाने, तीन नदी जोड़ो परियोजना से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई, माइक्रो इरीगेशन विस्तार, आधुनिक मंडियां, बीज परीक्षण लैब और फसल नुकसान सर्वे के लिए तहसील-स्तरीय मौसम केंद्र जैसी रोडमैप ने किसानों का मन मोह लिया है। भावांतर योजना का विस्तार कर सोयाबीन के बाद सरसों को शामिल किया गया, जबकि उड़द और मूंगफली पर समर्थन मूल्य के साथ बोनस दिए जाने की बड़ी घोषणा भी हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं। किसानों के हितों में लिए जा रहे अनेक निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि प्रदेश सरकार की किसान कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की भावांतर राशि की घोषणा से किसानों के चेहरे पर नई आशा, उत्साह और विश्वास का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन से मध्यप्रदेश में कृषि विकास योजनाएं तेजी से लागू हो रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार योजनाओं की पहुँच परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। मध्यप्रदेश को देश का इकलौता राज्य है जहां किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'स्वावलंबी गौशाला (कामधेनु) स्थापना नीति-2025' लागू की है। इसके तहत 5,000 से अधिक गायों वाली बड़ी आत्मनिर्भर गौशालाएं स्थापित करने की योजना है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में प्रदेश में दूध संग्रहण भी काफी बढ़ चुका है। सरकार ने शासकीय गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि बढ़ाई है और पशुधन रखने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश में अब तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी किये जाने पर सहमति बन चुकी है। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जायेगा। गेहूं उपार्जन में बारदान की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार, जूट कमिश्नर सहित अन्य बारदान प्रदाय एजेंसियों से बारदान आपूर्ति के लिए राज्य सरकार लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। कमिश्नर्स और कलेक्टर्स को मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समग्र किसान कल्याण पर जोर दिया है। पशुपालन, मत्स्य विकास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मोहन सरकार तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19 लाख 4 हजार 644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से एवं अन्य सभी संभागों में 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ होने जा रहा है।

राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव 2026

लेखक- विनोद कुमार सिंह

हमारा लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं,बल्कि जनचेतना की वह जीवंत धारा है , जो समय-समय पर अपने स्वरूप, अपने तेवर और अपनी दिशा को स्वयं निर्धारित करती है।वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों का प्रथम चरण - असम,केरल और केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सम्पन्न मतदान - इसी लोकतांत्रिक चेतना का प्रखर और व्यापक प्रतिबिंब बनकर सामने आया है।यह चरण केवल मतपेटियों तक सीमित एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि जनमत की वह गूंज है जिसमें सामाजिक परिवर्तन की आहट, राजनीतिक पुनर्संतुलन की छाया और भविष्य की राजनीति की स्पष्ट रूपरेखा सुनाई देती है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने इस लोकतांत्रिक उत्सव को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया है। असम में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान, केरल में लगभग 78 प्रतिशत और पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास रिकॉर्ड मतदान यह स्पष्ट संकेत देता है कि भारत का मतदाता अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय और निर्णायक भागीदार बन चुका है। यह आंकड़े केवल प्रतिशत नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास,उसकी प्रतिबद्धता और उसकी आकांक्षाओं का जीवंत प्रमाण हैं। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि वहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि जनसरोकारों की अभिव्यक्ति का मंच बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक जिस प्रकार मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, वह इस बात का द्योतक है कि मतदाता अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग और सचेत है।यह उत्साह जहां एक ओर सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि यदि सरकार ने अपने कार्यों से जनविश्वास अर्जित किया है,तो उसे पुनः अवसर भी मिल सकता है। केरल का मतदान प्रतिशत अपनी प्रकृति में भले ही संतुलित प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी गहराई में एक परिपक्व लोकतांत्रिक चेतना का प्रवाह दिखाई देता है।यहाँ का मतदाता परंपरागत रूप से विचारधारा आधारित मतदान करता है और यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत स्थिर रहते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत देता है। लगभग 78 प्रतिशत मतदान यह बताता है कि केरल में लोकतंत्र केवल एक प्रक्रिया नहीं,बल्कि एक वैचारिक अभ्यास है,जिसमें हर मतदाता अपने निर्णय को एक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। पुडुचेरी में लगभग 90 प्रतिशत के आसपास मतदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र का उत्साह क्षेत्रफल या जनसंख्या पर निर्भर नहीं करता,बल्कि जनभागीदारी की भावना पर आधारित होता है। छोटे से केन्द्र शासित प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान करना यह दर्शाता है कि लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। यह मतदान न केवल राजनीतिक दलों के लिए संदेश है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि लोकतंत्र की असली शक्ति जनता की सक्रिय भागीदारी में निहित है। इस प्रथम चरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मतदाता संरचना में हो रहा परिवर्तन है।लगभग 5.3 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोकतंत्र अब केवल संख्याओं का खेल नहीं, वरन विविधता और समावेश का उत्सव बन चुका है। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन का सबसे सशक्त संकेत है।केरल और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर या उससे अधिक होना केवल एक सांख्यिकीय तथ्य नहीं,बल्कि एक सामाजिक क्रांति का संकेत है। महिलाएं अब केवल मतदान करने वाली इकाई नहीं,बल्कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने वाली शक्ति बन चुकी हैं।उनके मुद्दे अब चुनावी विमर्श के केंद्र में हैं - चाहे वह महंगाई हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, शिक्षा हो या सुरक्षा।राजनीतिक दलों ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है और महिला मतदाताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं और घोषणाएं प्रस्तुत की हैं।यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में महिला मतदाता भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। युवा मतदाताओं की भागीदारी इस चुनाव की आत्मा है।लाखों नए मतदाताओं का पहली बार मतदान करना यह दर्शाता है कि भारत का भविष्य अब मतदान केंद्रों तक पहुंच चुका है। यह युवा वर्ग पारंपरिक राजनीति से अलग सोच रखता है।उसके लिए जातीय या धार्मिक समीकरणों की अपेक्षा रोजगार, शिक्षा, डिजिटल अवसर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक महत्वपूर्ण हैं।वह केवल वादों से प्रभावित नहीं होता,बल्कि परिणाम चाहता है,पारदर्शिता चाहता है और अवसर चाहता है। यही कारण है कि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि निर्णायक बन चुकी है। पुरुष मतदाताओं की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है,लेकिन महिला और युवा मतदाताओं के उभार ने चुनावी समीकरणों को अधिक संतुलित और प्रतिस्पर्धी बना दिया है।यह परिवर्तन लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है,क्योंकि इससे चुनाव अधिक निष्पक्ष और परिणाम अधिक प्रतिनिधिक बनते हैं। अगर हम वर्त्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो असम, केरल और पुडुचेरी तीनों ही क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के चुनावी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। असम में जहां भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है,वहीं केरल में पारंपरिक एल डी एफ (LDF) और यु डी एफ (UDF .)के बीच वैचारिक संघर्ष जारी है। पुडुचेरी में त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव को और अधिक जटिल और रोचक बना रहा है। असम में उच्च मतदान यह संकेत देता है कि चुनाव अत्यंत प्रतिस्पर्धी है।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन अपने लाभार्थी वर्ग और महिला मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने में सफल रहता है,तो उसे बढ़त मिल सकती है ,लेकिन उच्च मतदान अक्सर सत्ता विरोधी भावना का भी संकेत होता है, जिससे चुनाव परिणाम अनिश्चित हो जाता है। केरल में स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वहां का मतदाता अत्यंत जागरूक और वैचारिक है।यहाँ चुनाव परिणाम बहुत ही सूक्ष्म अंतर से तय होते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में हैं।पुडुचेरी में रिकॉर्ड मतदान यह संकेत देता है कि मतदाता परिवर्तन चाहता है या स्पष्ट जनादेश देना चाहता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के कारण यहां हंग असेंबली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतदान प्रतिशत के भीतर छिपे राजनीतिक संकेतों को यदि समझा जाए कि उच्च मतदान केवल संख्या नहीं,बल्कि एक संदेश है।यह संदेश कभी बदलाव का होता है, कभी समर्थन का और कभी संतुलन का।महिला मतदाताओं की सक्रियता यह दर्शाती है कि कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा अब राजनीति के केंद्र में हैं।युवा मतदाताओं की भागीदारी यह बताती है कि भविष्य की राजनीति विकास और अवसरों के इर्द-गिर्द घूमेगी। प्रथम चरण का यह मतदान यह भी स्पष्ट करता है कि भारतीय लोकतंत्र अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है।यह दौर परंपरागत समीकरणों से आगे बढ़कर विकास,पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित है।

सत्यशोधक ज्योतिबा फुलेः जिनके विचारों ने बदली समाज की दिशा

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो किसी भव्य इमारत की नींव में ईंट बनकर समा जाते हैं। लेकिन जब-जब आधुनिक भारत में न्याय और बराबरी की बात होगी, ज्योतिबा फुले का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। फुले कोई पारंपरिक नेता नहीं थे, वे एक ऐसे दूरद्रष्टा शिक्षक थे जिन्होंने ब्लैकबोर्ड पर अक्षर लिखने से पहले समाज की कड़वी सच्चाइयों और गरीबों के आंसू पढ़ना सीखा था। आज हम जिस आधुनिक भारत में सांस ले रहे हैं, जहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और समाज का हर वर्ग तरक्की के सपने देख रहा है, उसकी पहली मजबूत ईंट 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने ही रखी थी।वह एक ऐसा दौर था जब शिक्षा पर कुछ खास लोगों का एकाधिकार था और समाज की एक बहुत बड़ी आबादी अज्ञानता के घने अंधेरे में कैद थी। ज्योतिबा ने बहुत कम उम्र में ही यह समझ लिया था कि किसी को गुलाम बनाने के लिए लोहे की जंजीरें जरूरी नहीं होतीं, बल्कि उसे अशिक्षा के पिंजरे में कैद रखना ही काफी होता है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से समाज को आईना दिखाते हुए कहा था- शिक्षा के बिना इंसान की बुद्धि मर जाती है और बुद्धि के बिना उसका विकास और नैतिकता हमेशा के लिए रुक जाती है। ज्योतिबा फुले के जीवन का सबसे साहसी अध्याय उनकी जीवनसंगिनी सावित्रीबाई फुले के साथ जुड़ा है। उन्होंने किसी बड़े मंच से केवल भाषण देने के बजाय, बदलाव की शुरुआत अपने घर से की। उस कट्टर समाज की कल्पना कीजिए, जहाँ औरतों का पढ़ना एक महापाप माना जाता था, वहाँ ज्योतिबा अपनी पत्नी के हाथ में कलम और किताब थमा रहे थे। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने निकलती थीं और उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, तो ज्योतिबा एक चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े रहते थे। यह उन दोनों का अटूट साहस और जिद ही थी, जिसने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल का रास्ता खोला और सदियों पुराने बंद दरवाजे हमेशा के लिए तोड़ दिए। फुले के सुधार केवल स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहे। उनकी पैनी नजर समाज की हर उस बुराई पर थी जो एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा समझती थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को अंधविश्वासों के मानसिक चंगुल से बाहर निकालना था। वे केवल बातों के धनी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को जीकर दिखाया। जब अछूतों के लिए पानी पीना भी अपराध माना जाता था, तब उन्होंने अपने खुद के घर का पानी का टैंक उनके लिए खोल दिया। यह उस समय के कट्टरपंथी समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। वे जानते थे कि जब तक एक आम इंसान अपनी नजरों में खुद को गौरवशाली नहीं समझेगा, तब तक वह समाज में अपना हक कभी नहीं मांग पाएगा। अक्सर हम फुले को इतिहास की एक पुरानी तस्वीर मानकर दीवार पर टांग देते हैं, लेकिन उनके विचार आज के आधुनिक युग में भी उतने ही अनिवार्य हैं। आज हमारे पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां तो हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर वह सामाजिक चेतना है जो फुले पैदा करना चाहते थे? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा का असली मकसद केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि खुद को स्वतंत्र बनाना और समाज के प्रति संवेदनशील होना है। आज जब हम समाज में बढ़ती नफरत और भेदभाव की नई दीवारें देखते हैं, तो फुले की गुलामगिरी जैसी कालजयी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली मानसिक आजादी पाना अभी भी एक लंबा संघर्ष है। महात्मा फुले ने कभी अपने व्यक्तिगत सुख या आराम की चिंता नहीं की। अपनी प्रतिभा और पढ़ाई के दम पर वे चाहते तो एक बहुत ही समृद्ध जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के लिए कांटों भरा रास्ता चुना जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे। यही कारण है कि जनता ने उन्हें अपने दिल से महात्मा की उपाधि दी थी। उनकी लड़ाई किसी विशेष धर्म या जाति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी जंग उस अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध थी जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच-नीच की दीवार खड़ी करती थी। वे किसानों के दुख-दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से समझते थे और उनके शोषण के खिलाफ हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे। 11 अप्रैल का यह दिन हमें रुककर यह आत्मचिंतन करने का मौका देता है कि हम फुले के सपनों के भारत के कितने करीब पहुँचे हैं। क्या आज हर गांव के बच्चे के हाथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या आज भी हमारी महिलाएं समाज में पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करती हैं? महात्मा फुले ने जो मशाल डेढ़ सौ साल पहले जलाई थी, उसे बुझने न देना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए, आज हम फुले के उन सिद्धांतों को याद करें जो कहते हैं कि ज्ञान ही वह एकमात्र प्रकाश है जो हमें अंधकार से बाहर निकालकर सम्मान का जीवन दिला सकता है। उनका संघर्ष हमें भरोसा दिलाता है कि अगर हमारे इरादे नेक हों, तो एक अकेला व्यक्ति भी वक्त की धारा को मोड़ने का दम रखता है।

आयुष शेट्टी ने विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टी को हराया

सेमीफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के आयुष शेट्टी ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। आयुष शेट्टी पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को मात दी है। भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया। इस तरह आयुष ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 25वीं रैंकिंग के शेट्टी ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रिस्टी को 23–21, 21–17 को हराया। टूर स्तर पर शेट्टी और क्रिस्टी के बीच यह पहला मुकाबला था। क्रिस्टी एशियाई खेलों और एशियन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। इतना ही वह 2020 में थॉमस कप जीतने वाली इंडोनेशियाई टीम का भी हिस्सा थे। यूएस ओपस सुपर 300 के गत चैंपियन शेट्टी ने इससे पहले गुरुवार को राउड ऑफ 16 में चीनी ताइपे के 20वीं रैंकिंग के ची यू जेन को हराया था।

बिली जीन किंग कप

इंडोनेशिया से हारा भारत, कोरिया की जीत का सिलसिला जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। बिली जीन किंग कप ग्रुप–ड्ड एशिया/ओशिआना मुकाबलों में भारत को गुरुवार को इंडोनेशिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में इंडोनेशिया ने दोनों सिंगल्स मैच जीतकर अजेय बढ़त हासिल कर ली। पहले सिंगल्स मुकाबले में वैष्णवी अडकर को प्रिस्का मैडेलिन नुग्रोहो के खिलाफ कड़े मुकाबले में 7–6(3), 6–7(3), 6–3 से हार झेलनी पड़ी। मैच काफी उतार–चढ़ाव भरा रहा, जहां अडकर ने दूसरे सेट में वापसी करते हुए मुकाबला निर्णायक सेट तक पहुंचाया, लेकिन तीसरे सेट में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने बाजी मार ली। दूसरे सिंगल्स में सहजा यमलापल्ली को जेनिस त्जेन के खिलाफ 6–2, 6–1 से एकतरफा हार का सामना करना पड़ा, जिससे इंडोनेशिया ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। खबर लिखे जाने तक रुतुजा भोसले और अंकिता रैना इंडोनेशियाई जोड़ी के खिलाफ डबल्स मुकाबला खेल रही थीं। अन्य मुकाबलों में कोरिया गणराज्य ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। दायोन बैक ने वैलेंटिना इवानोव को 7–5, 6–3 से हराया, जबकि सोह्युन पार्क ने मोनिक बैरी को 6–0, 6–1 से हराकर टीम की जीत पक्की कर दी। कोरिया और इंडोनेशिया दोनों ही टीमें अब तक अपने सभी मुकाबले जीतकर तालिका में शीर्ष पर बनी हुई हैं। वहीं थाईलैंड ने भी शानदार वापसी करते हुए मंगोलिया को 3–0 से क्लीन स्वीप किया।

यूईएफए यूरोपा लीग

क्वार्टरफाइनल के पहले लेग में

ब्रागा और रियल बेटिस के बीच मैच 1-1 से ड्रॉ रहा

ब्रागा, एजेंसी। यूईएफए यूरोपा लीग क्वार्टरफाइनल के पहले लेग में ब्रागा और रियल बेटिस के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। एस्टाडियो म्युनिसिपल डे ब्रागा में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच की शुरुआत में ब्रागा ने आक्रामक अंदाज अपनाया और इसका फायदा उन्हें जल्दी ही मिल गया। डिएगो रोड्रिग्स के कॉर्नर पर फ्लोरियन ग्रिलिट्श ने शानदार फ्लिक के जरिए गोल दागते हुए टीम को बढ़त दिलाई। इस शुरुआती गोल ने घरेलू टीम को आत्मविश्वास दिया और उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि, रियल बेटिस ने धीरे-धीरे वापसी की कोशिश की। 24वें मिनट में मार्क बार्ट्रा ने हेडर के जरिए बराबरी का मौका बनाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर बाहर चली गई। इसके बाद भी बेटिस ने दबाव बनाए रखा और ब्रागा के गोलकीपर लुकास हॉर्निसेक को कई बार सतर्क रहना पड़ा, खासकर कुचो हर्नांडेज के क्लोज-रेंज हेडर को रोकते

समय। दूसरे हाफ में मैच और रोमांचक हो गया। बेटिस ने आक्रमण को तेज करने के लिए बदलाव किए, जिसमें विंगर एंटनी को मैदान पर उतारा गया। हालांकि, ब्रागा ने भी मौके बनाए और ग्रिलिट्श का एक शॉट गोलकीपर पाऊ लोपेज ने शानदार तरीके से बचाया। मैच का टर्निंग पॉइंट तब आया जब ब्रागा के जीन-बैप्टिस्ट गोर्बी ने बॉक्स में फाउल कर दिया, जिससे बेटिस को पेनल्टी मिली। कुचो हर्नांडेज ने इस मौके को भुनाते हुए गेंद को बाएं कोने में डालकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने जीत के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई और गोल नहीं हो सका। अब यह मुकाबला दूसरे लेग में तय होगा, जो 16 अप्रैल को सेविले में खेला जाएगा।

इस ड्रॉ के साथ, दोनों टीमों के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का बराबर मौका है, जहां उनका सामना एससी फ्रीबर्ग या सेल्टा विगो से हो सकता है। वहीं, फाइनल 20 मई को बेसिकटास पार्क, इस्तांबुल में आयोजित होगा।

रोज 100–150 छक्कों की प्रैक्टिस...

धोनी स्टाइल हेलिकॉप्टर से वार, ये है मुकुल चौधरी का 'फिनिशर फॉर्मूला'

नई दिल्ली, एजेंसी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गुरुवार रात, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स लगभग हार की कगार पर थी, तब मुकुल ने 27 गेंदों में नाबाद 54 रन ठोककर मैच पलट दिया. 24 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे, टीम के 7 विकेट गिर चुके थे... और सामने सिर्फ टेलेंडर्स. शुरुआत भी आसान नहीं रही- पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन. लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो 'फिनिशर मोड' था- अगली 22 गेंदों में 53 रन, जिसमें 7 छक्के शामिल थे.

मुकुल ने मैच के बाद बताया, 'मैंने ये शॉट बचपन से प्रैक्टिस किया है. मुझे हमेशा धोनी का फिनिशिंग स्टाइल पसंद रहा. वो यॉर्कर पर भी छक्का मार देते थे... और जब आप ऐसा करते हैं, तो गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो जाता है.'

17वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर लगाया गया हेलिकॉप्टर शॉट इस पारी का टर्निंग पॉइंट बना.

ताकत + मेहनत = मुकुल का फॉर्मूला

मुकुल की ताकत सिर्फ नेचुरल पावर नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत का नतीजा है. उन्होंने खुद कहा, मेरी बॉडी थोड़ी पावरफुल है, लेकिन मैं रोज 100-150 छक्कों की प्रैक्टिस करता हूं. इससे बैट स्पीड डेवलप होती है. पिछले 5-6 महीनों से मैंने इस पर बहुत काम किया है.'

पहले ही दे चुके थे संकेत

आईपीएल से पहले ही मुकुल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमें अपनी झलक दिखा दी थी. उन्होंने राजस्थान की ओर से खेलते हुए दिल्ली के खिलाफ रनों की बारिश कर दी थी.

- 26 गेंदों में नाबाद 62 रन – 238.46 का स्ट्राइक रेट
- 7 छक्के, 1 चौका
- 176 रन के लक्ष्य का सफल पीछा

इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 198.85 रहा, जो बताता है कि ये 'वन–नाइट वंडर' नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ फिनिशर है.

3 ओवर में 4 रन और 9 विकेट, ब्राजील की गेंदबाज ने रचा इतिहास

13 पर सिमटी विपक्षी टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्राजील की तेज गेंदबाज लॉरा कारडोसो ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया जब वह पुरुषों या महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ही पारी में नौ विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं। कारडोसो ने लेसोथो के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए चार रन देकर नौ विकेट चटकाए जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े है। लेसोथो की टीम 13 रन पर सिमट गई।

लॉरा कारडोसो ने गैबोरोन में बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल दो मैदान पर बीसीए कालाहारी महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की। पिछला रिकॉर्ड भूटान की सोनम येशे के नाम था जिन्होंने 2025 में पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में म्यांमार के खिलाफ सात रन देकर आठ विकेट लिए थे।

कारडोसो ने इंडोनेशिया की खिलाड़ी को छोड़ा पीछे– अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार महिलाओं के टी20 अंतरराष्ट्रीय में कारडोसो ने इंडोनेशिया की रोहमालिया के 2024 में मंगोलिया के खिलाफ बिना रन के सात विकेट चटकाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। गुरुवार को हुए मैच में ब्राजील ने रॉबर्टा एवरी (35 गेंद पर 48 रन) और मोनिके मचाडो (41 गेंद पर नाबाद 69 रन) की शानदार पारियों की मदद से 202 रन का बड़ा स्कोर बनाया।

रिंग में विरोधियों को धूल चटाने वाली बॉक्सर नूपुर श्योराण ने रैंप वॉक में बिखेरा जलवा

नई दिल्ली, एजेंसी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट बॉक्सर नूपुर श्योराण ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था. इसमें वह साड़ी में रैंप वॉक करती बेहद खूबसूरत नजर आई. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट नूपुर श्योराण ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह रैंप वॉक कर रही थी. लाल रंग की साड़ी में वह बेहद खूबसूरत और किसी हिरोइन से कम नहीं लग रही थी. ये वीडियो उन्होंने जनवरी में शेयर किया था. फैंस ने भी इस वीडियो को खूब प्यार दिया और एक यूजर ने लिखा, 'आप रवीना टंडन की तरह लग रही हों.' इसी इवेंट का उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, 'आपको कोम्प्रोमाईज़ नहीं करना चाहिए, जब आप दोनों चीजें कर सकती हों.' वीडियो के पहले हिस्से में वह बॉक्सिंग कर रही हैं और दूसरे हिस्से में रैंप वॉक. लाल रंग की साड़ी, खुले बालों के साथ लाल रंग की बिंदी, उनपर जच रही थी.

नूपुर श्योराण का जन्म 26 सितंबर, 1998 को हरियाणा के भिवानी में हुआ था. उन्होंने एक बार बताया था कि उन्हें बॉक्सिंग की प्रेरणा उनके पिता और दादाजी से मिली. 2005 में उनके पापा ने एक अकैडमी शुरू की, जिसमें काफी ऐसे बच्चे आते थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी. जब वह मैडल लेकर आते थे, तब उन्हें देखकर ही नूपुर ने सोचा था कि उन्हें भी बॉक्सर बनना है. नूपुर श्योराण ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉक्सिंग शुरू की. वह अब रेलवे में जॉब करती हैं. 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन नूपुर ने 2024 में महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. 2025, अस्ताना वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था.

व्यापार

1 पर 1 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में भी बंटने जा रहा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट तय

मुंबई, एजेंसी। शेयर आज शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में फोकस में रहेंगे। कंपनी के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। इस कंपनी ने बोनस शेयर देने का भी फैसला किया। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बांटा जाएगा। बता दें, कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा गया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 24 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार शेयर 24 अप्रैल 2026 को ही एक्स–बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 1 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा। बता दें, कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। शेयर बीएसई में 2.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 121.90 रुपये के स्तर पर था। पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7.26 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में यह स्टॉक 3.94 प्रतिशत नीचे गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 172 रुपये और 52 वीक लो लेवल 86.98 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 647.92 करोड़ रुपये का है। दिसंबर तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.68 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 47.32 प्रतिशत हिस्सा था।

सोना-चांदी के गिरे भाव, 152561 पर आया गोल्ड, सिल्वर 242067 पर पहुंची

मुंबई, एजेंसी। घरेलू मार्केट में सोने–चांदी के भाव में आज गिरावट है। शुक्रवार, 10 अप्रैल को एमसीएक्स पर चांदी 0.7 प्रतिशत गिरकर 2,42,067 प्रति किलो पर आ गई। जबकि, गोल्ड 0.56 प्रतिशत गिरकर 1,52,561 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में सोने–चांदी का मिलाजुला रुख देखने को मिला। स्पॉट सिल्वर जहां 0.1 प्रतिशत बढ़कर 75.11 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं, स्पॉट गोल्ड 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,755.84 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 0.8 प्रतिशत गिरकर 4,779.20 डॉलर पर आ गया। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। जैसे डॉलर की मजबूती, भू–राजनीतिक तनाव में नरमी, निवेशकों द्वारा अन्य बाजारों में नुकसान की भरपाई और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होना। दरअसल, सोना एक नॉन–यील्डिंग एसेट है, इसलिए जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो इसकी मांग कम हो जाती है। ईरान युद्ध से जुड़े मुद्दे अब भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। शनिवार को इस्लामाबाद में अहम बातचीत होने जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे। इसमें ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। इस बीच, होर्मुज में शुल्क को लेकर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी है। वहीं, लेबनान में इजरायली हमलों से संघर्ष विराम पर भी खतरा मंडरा रहा है। महंगाई और फेड की नीति पर असर : छह सप्ताह से जारी युद्ध ने महंगाई के रिस्क को बढ़ा दिया है। इससे केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को टाल सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, फरवरी में उपभोक्ता खर्च में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है।

भारत में गैस संकट: कांच उद्योग पर युद्ध का कहर, फिरोजाबाद से लेकर देशभर में असर

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु की कंपनी को-फाउंडर शिशिर साथ्यान पिछले एक महीने से अपने प्रीमियम ड्रिंक्स के लिए कांच की बोतलें जुटाने में परेशान हैं। उनका कहना है कि बाजार में अब कांच के फ्लास्क मिल ही नहीं रहे हैं, जबकि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की मांग सबसे ज्यादा होती है। बढ़ती लागत को संभालने के लिए कंपनी अब मार्केटिंग और डिस्काउंट बजट में कटौती करने पर मजबूर हो गई है। देश में कांच की कमी की सबसे बड़ी वजह गैस संकट है। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए सप्लाई फैक्ट्रियों से हटाकर घरों की ओर मोड़ दी है। इसका सीधा असर कांच बनाने वाले उद्योगों पर पड़ा है, जो गैस पर निर्भर होते हैं।

पिछले 400 साल से कांच उद्योग का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद इस संकट का सबसे बड़ा शिकार बना है। यहां के कारखाने नेचुरल गैस से चलते हैं। कांच बनाने की भट्टियां 1500एष्ट तापमान पर लगातार चलती रहती हैं। अगर ये ठंडी पड़ जाएं तो दोबारा चालू करने में हफ्तों का

समय और अरबों रुपये का खर्च लगता है।

गैस सप्लाई कम होने के कारण कई कंपनियों को उत्पादन 50 प्रतिशत तक घटाना पड़ा है। कांच की कीमतें 20 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। कई कंपनियों ने नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है और विस्तार योजनाएं रोक दी गई हैं। ग्लोबल कंपनियों को सप्लाई करने वाले उद्योग भी इस संकट से जूझ रहे हैं। कांच की कमी का असर सिर्फ बोतलों तक सीमित नहीं है। दूध की बोतलें, जैम के जार, दवाइयों की शीशियां, कॉस्मेटिक पैकेजिंग, सबकी सप्लाई प्रभावित हुई है। कुछ कंपनियों को पैकेजिंग लागत 30 प्रतिशत तक बढ़ानी पड़ी है। एस आर ग्लास के प्रबंध निदेशक प्रांजल मित्तल को उम्मीद है कि कांच उत्पादन में यह रुकावट महीनों तक चलेगा। उनका कहना है, 'अगर युद्ध एक सप्ताह बढ़ता है, तो हमारा कारोबार एक महीने के लिए गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब है कि अभी अगले चार महीने बिगड़ चुके हैं। '

भारत की क्या है कमजोरी

भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। लगभग 50 प्रतिशत नेचुरल गैस आयात होती है। करीब 40 प्रतिशत सिर्फ कतर से आता है। लगभग 90 प्रतिशत आयात मिडिल-ईस्ट से होता है। यही वजह है कि वैश्विक संकट का सीधा असर घरेलू उद्योगों पर पड़ रहा है। गैस की कमी का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है। रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटे फूड बिजनेस भी की कमी से जूझ रहे हैं। इसका असर शादी सीजन और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिख रहा है। हालांकि सीजफायर की घोषणा हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात जल्द सामान्य नहीं होंगे। ग्लास इंडस्ट्रीज से जुड़े कारोबारी मानते हैं कि अगर युद्ध एक हफ्ता भी बढ़ता है, तो इसका असर कई महीनों तक चलता है।

85 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया था शेयर, अब दो महीने से भी कम में 70 प्रतिशत उछला शेयर का दाम

नई दिल्ली, एजेंसी। 85 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़कने के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने जबरदस्त वापसी की है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के शेयर गुरुवार को 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 36.34 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर टूटकर 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया था। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अब इस लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 71.24 रुपये है।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 85 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 20 अगस्त 2024 को 157.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 2 मार्च 2026 को 21.21 रुपये पर जा पहुंचे थे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 9 अगस्त 2024 को बाजार में लिस्ट हुए थे। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप गुरुवार 9 अप्रैल को 16000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में पिछले 5 दिन में 42 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 2 अप्रैल 2026 को 25.59 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 अप्रैल 2026 को 36.34 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर इस साल 30 मार्च से देखें तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 59 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 22.80 रुपये से 36 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में

56 पर्सेंट की तेजी आई है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 2 अगस्त 2024 को खुला था और यह 6 अगस्त तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 76 रुपये था। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ टोटल 4.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स का कोटा 4.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 12.38 गुना दांव लगा था। आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 2.51 गुना दांव लगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)